सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

जुलाई 2020 ■ ₹ 30

- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
- पीएम स्व-निधि योजना
- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020
- भारतमार्केट
- ओपन स्काइज संधि
- लिपुलेख-कालापानी विवाद
- भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन











- इन्हें भी जानें
- पत्र-पत्रिका संपादकीय
- संस्थान-संगठन
- समसामयिक प्रश्न
- लोक सभा-राज्य सभा प्रश्नोत्तर सार

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

2020 संस्करण

हल प्रश्न पत्र

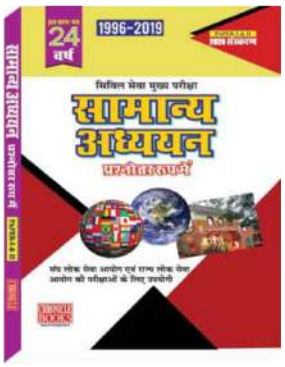

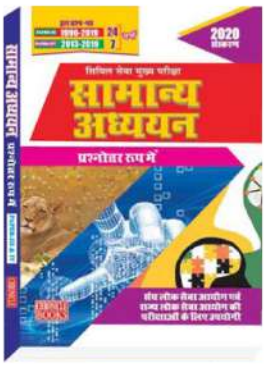





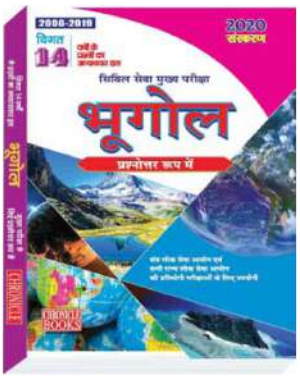

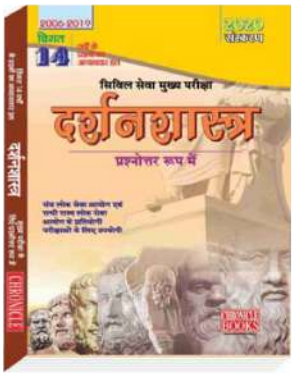

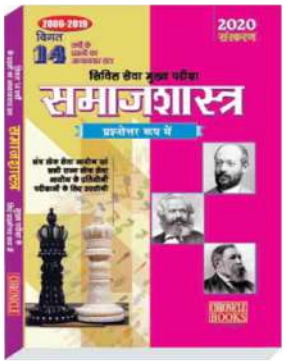

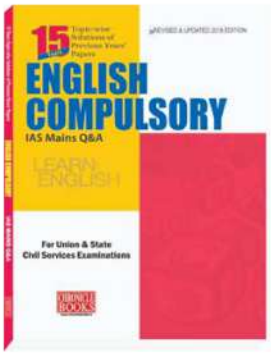

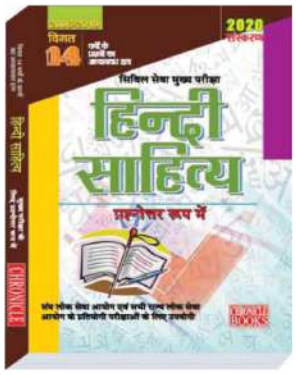

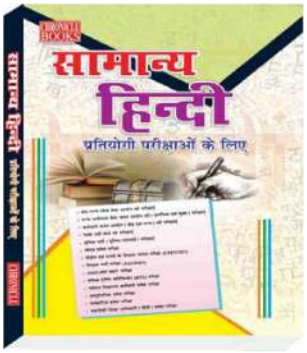

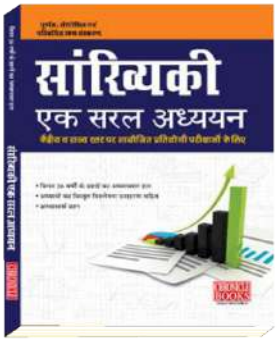

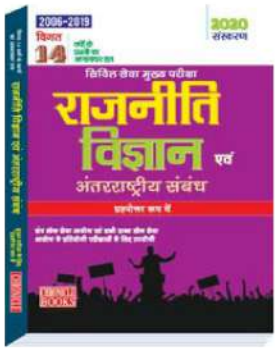

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

आपकी सफलता का मार्गदर्शक

आईएएस तथा पीसीएस परीक्षाओं, यू.जी.सी. की जे.आर.एफ./नेट परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी



2020 संस्करण

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514611/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

टू द पॉइंट

NCERT Plus

6 भागों में

2020 संस्करण

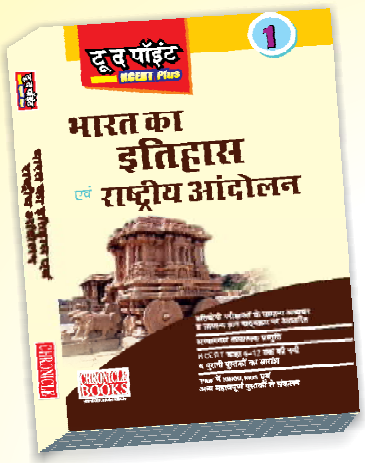

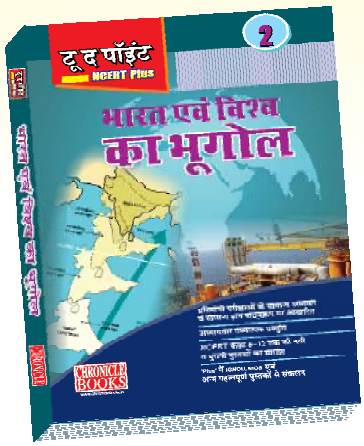

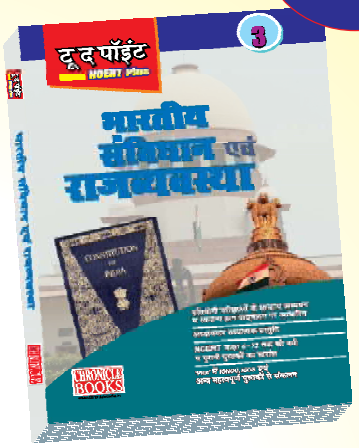

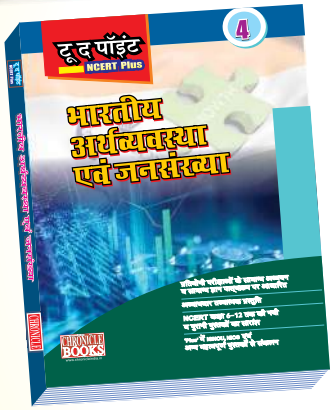

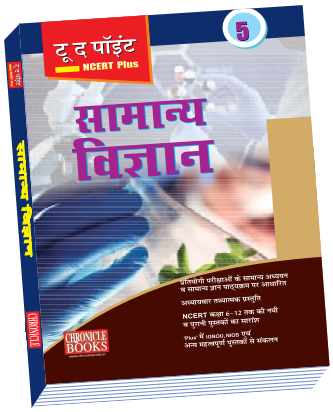



इस पुस्तक को टू द पॉइंट रूप में सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान (GK/GS) की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर व NCERT की सामग्रियों को समाहित कर तैयार किया गया है। इसमें NCERT कक्षा 6-12 की नई व पुरानी पुस्तकों तथा IGNOU, NIOS, राज्य बोर्ड एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों से सामग्री संकलित की गई है।

NCERT, IGNOU, NIOS व State Board द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ., कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएड, राज्य कर्मचारी चयन आयोग व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, ओलंपियाड के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रवेश परीक्षाओं जैसे- CLAT, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

CHRONICLE BOOKS

Corporate Office

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12,Mob.: 9953007630
E-mail: circulation@chronicleindia.in, info@chronicleindia.in

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

जुलाई 2020 | वर्ष : 7 | अंक : 5

इस अंक में...

लोक सभा राज्य सभा प्रश्नोत्तर-सार 54

इन्हें भी जानें 55



06 आर्थिकी

- आत्मनिर्भर भारत
- एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता उपाय
- कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार हेतु उपाय
- आठ क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु उपाय
- राज्यों द्वारा श्रम कानून बदलाव
- मौद्रिक नीति समिति का संकल्प
- एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव
- भारतमार्केट
- द सरस कलेक्शन
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

12 राष्ट्रीय

- भारत में टिड्डियों का खतरा
- स्टाइरीन गैस रिसाव
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा 3100 करोड़ रुपए आवंटित
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना
- कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
- भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली 'मेड इन इंडिया' इंजन
- पीएम स्व-निधि योजना
- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड
- अटल पेंशन योजना के पांच वर्ष
- ईआरपी 'समर्थ'
- कार्यक्रम 'गोल'
- नए भौगोलिक संकेतक टैग
- नई संसद परियोजना को मंजूरी

18 अंतरराष्ट्रीय

- भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन
- जी-7 शिखर सम्मेलन स्थगित
- 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020
- कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल
- लिपुलेख-कालापानी विवाद
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020
- ओपन स्काइज संधि
- यूरोपीय संघ का कोविड-19 रिकवरी फंड
- चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने संबंधित विधेयक
- चीन द्वारा हांगकांग संबंधित विवादास्पद कानून पारित

22 विज्ञान-पर्यावरण

- 'नगर वन' विकसित करने की शहरी वन योजना
- आईएनएलसीयू एल57
- तेजस एमके-1 एफओसी विमान
- कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपरमॉडल
- रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ
- मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ'
- बृहस्पति के पास खोजा गया क्षुद्रग्रह
- आईसीजीएस सचेत
- सुपर अर्थ ग्रह
- 'स्वस्थवायु' वेंटिलेटर

28 BFSI

30 बिजनेस

31 राज्य

34 खेल

37 सार-संक्षेप

49 संस्थान-संगठन

50 पत्र-पत्रिका संपादकीय

52 समसामयिक प्रश्न

संपादक
एन.एन. ओझा
e-mail: info@chronicleindia.in

विज्ञापन
अध्यक्ष
संजीव नन्दक्योलियार
advt@chronicleindia.in
Ph. 9953007627, 9891601320

प्रसार
महाप्रबंधक
अरविन्द मिश्र
सहायक महाप्रबंधक
पंकज पांडेय
circulation@chronicleindia.in
Mob.: 9953007630
subscription@chronicleindia.in
Mob.: 0-9953007629

व्यावसायिक कार्यालय
क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27डी, सेक्टर-16
नोएडा-201301
फोन: 0120-2514611-12

सर्वाधिकार सुरक्षित (c) क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि. न्यायिक-क्षेत्र दिल्ली।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा**। द्वारा एच-31, प्रथम तल, ग्रीन पार्क एक्स. नयी दिल्ली - 110016, से प्रकाशित एवं रत्ना ऑफसेट, सी-101, ओखला फेस 2, नई दिल्ली, से मुद्रित। **संपादक. एन.एन.ओझा**

आर्थिकी



आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोविड-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है।

- यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केन्द्रित है तथा यह कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ: आत्मनिर्भर भारत पांच स्तंभों पर आधारित होगा।

1) अर्थव्यवस्था- जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर लंबी उछाल आधारित हो;
2) अवसंरचना - ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने;
3) प्रणाली (सिस्टम)- एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की नीति पर नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली प्रौद्योगिकी संचालित (Technology Driven) व्यवस्थाओं पर आधारित हो;
4) जीवंत जनसांख्यिकी- जीवंत जनसांख्यिकी (Vibrant Demography) दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है;
5) मांग- भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई, 2020 को कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत पहले भाग में व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन उपायों के तहत एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा; कर्ज के बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अप्रधान ऋण (Subordinate Debt)।

- सरकार एक 'एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स' स्थापित करेगी, जिसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी; एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय तथा 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा।
- एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई (Non-Banking Financial companies / Housing finance companies / Microfinance institutions) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना; एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की 'आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0'।
- डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी। व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'स्रोत पर कर कटौती' और 'स्रोत पर संग्रहीत कर' की दरों में 25% की कटौती की जाएगी।

प्रवासियों तथा किसानों की सहायता हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत दूसरे भाग में प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर) सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रवासी श्रमिकों को दो माह तक मुफ्त अनाज तथा प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग द्वारा मार्च 2021 तक देशभर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन (पीडीएस) प्राप्त करने में सक्षम बनया जाएगा-'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'।

- प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना; 'शिशु मुद्रा' के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

- रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा, जिसमें प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी।
- पीएमएवाई (शहरी) के तहत 'मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना' के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।
- कैम्पा (Compensatory Afforestation Management - Planning Authority- CAMPA) फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये; नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की 'अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी' प्रदान की जाएगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ शिशु मुद्रा ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये का है। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2019-20

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2019-20 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 15 मई, 2020 को जारी किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2019-20 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है।

- 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 8.17 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान गेहूँ का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 107.18 मिलियन टन अनुमानित है। जो विगत पांच वर्षों के औसत गेहूं उत्पादन की तुलना में 11.02 मिलियन टन अधिक है।
- पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन रिकॉर्ड 47.54 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पाँच वर्षों के औसत पोषक/मोटे अनाजों के उत्पादन की तुलना में 4.50 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 23.01 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 2.19 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 33.50 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.10 मिलियन टन अधिक है।
- 2018-19 के दौरान 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था।

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार हेतु उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत तीसरे भाग में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: किसानों के लिए कृषि द्वार (फार्म-गेट) अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष; सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (Micro food enterprises) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- खुरपका मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 13,343 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने हेतु 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान; औषधीय या हर्बल खेती को बढ़ावा देने हेतु 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान; मधुमक्खी पालन संबंधी पहल हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 'टॉप' (Tomatoes] Onion and Potatoes -TOP) से 'टोटल' (सम्पूर्ण) तक 500 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित 'ऑपरेशन ग्रीन्स' को टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 में 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की घोषणा की गई थी।

कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार हेतु उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत तीसरे भाग में कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार हेतु उपायों की घोषणा की।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन: आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा।

- अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदा, कीमतों में वृद्धि के साथ अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी कोई स्टॉक सीमा संसाधक

या मूल्य श्रृंखला के भागीदारों (Processors or value chain participant) पर लागू नहीं होगी।

कृषि विपणन सुधार: किसानों को विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा ताकि किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प; निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार; कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा सुनिश्चित हो सके।

अनुबंध खेती के लिए नया कानून: सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधकों, समूहकों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए, एक सुविधाजनक कानूनी संरचना को अंतिम रूप देगी। इस कदम से अनुबंध खेती (Contract Farming) करने में सहायता होगी।

जीके फैक्ट

✧ कृषि उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए, अक्सर पूर्व निर्धारित कीमतों पर किसानों और प्रसंस्करण और / या विपणन फर्मों के बीच समझौते को अनुबंध खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है।

आठ क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु उपाय

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे भाग में 16 मई, 2020 को 8 क्षेत्रों- कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में ढांचागत सुधारों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश, विविध अवसर तथा उदार व्यवस्था; खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा और नीतिगत सुधार किए जाएंगे।

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु मेक इन इंडिया को बढ़ावा तथा स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी।
- आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाया जाएगा।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागेदारी के आधार पर परिचालन और रखरखाव के लिए दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान; विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।
- केंद्र-शासित प्रदेशों में बिजली विभाग/उपदेयताओं का निजीकरण करने का निर्णय; उपभोक्ता अधिकार, विद्युत उद्योग को बढ़ावा तथा विद्युत क्षेत्र की स्थिरता सुधारों का खाका खींचने वाली टैरिफ नीति जारी की जाएगी।
- सामाजिक अवसंरचना में संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (Viability Gap Funding) के माध्यम से 8100 करोड़ परिव्यय के साथ निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने के लिए, चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा।

सात सेक्टरों में सरकारी सुधार और सहायक उपाय

17 मई, 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पांचवें भाग में 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की।

रोजगार: रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सुधार: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करके जमीनी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा।

- सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लॉक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ स्थापित किए जाएंगे।

प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा: डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा तक बहु-माध्यम पहुंच के लिए एक कार्यक्रम 'पीएम ई-विद्या' को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

- मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों का मनोवैज्ञानिक सहयोग करने के लिए एक पहल 'मनोदर्पण' तत्काल शुरू की जाएगी।

उद्योग: दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जाएगा। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।

कारोबार सुगमता: स्वीकृत विदेशी बाजारों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम: सरकार नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा करेगी, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) की संख्या आमतौर पर केवल एक से चार होगी, जबकि गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में पीएसई का निजीकरण किया जाएगा।

राज्यों को सहायता: केंद्र सरकार ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% करने का निर्णय लिया है।

राज्यों द्वारा श्रम कानून बदलाव

मई 2020 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कई भारतीय राज्यों द्वारा शुरू किए गए श्रम कानून संशोधनों और छूट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने

तीन साल के लिए श्रम कानूनों में व्यापक संशोधन या छूट देने की घोषणा की है।

- जबकि अन्य राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और ओडिशा ने तीन माह के लिए प्रति दिन काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ा दिये।
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अब विस्तारित कार्य समय पर आदेश को वापस ले लिया है, इसे दिन के आठ घंटे तक सीमित कर दिया है।
- 14 मई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने श्रम कानून संशोधनों के चलते श्रमिकों की दुर्दशा और 'आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144' के उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए जिनेवा स्थित आईएलओ से हस्तक्षेप की मांग की थी।
- ज्ञात हो कि भारत 'आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144' का हस्ताक्षरकर्ता है, जो सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय परामर्श के लिए कहता है।

जीके फैक्ट

✧ 'आईएलओ कन्वेंशन संख्या 87' संघ की स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom of Association) से संबंधित है।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

22 मई, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए।

महत्वपूर्ण तथ्य: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40% से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0% किया गया है। तदनुसार सीमांत स्थाई सुविधा दर और बैंक दर 4.65% से घटकर 4.25% हो गई। इसके तहत रिवर्स रेपो दर 3.75% से घटकर 3.35% हो गई।

- मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो उदार रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

घरेलू अर्थव्यवस्था: इस साल (8 मई तक) वाणिज्यिक पत्रों, बॉन्ड, डिबेंचर और कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में 66,757 करोड़ रुपये की तेजी से वृद्धि हुई।

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 2020-21 में अब तक 9.2 बिलियन डॉलर (15 मई 2020 तक) बढ़कर 12 महीने के आयात के बराबर 487.0 बिलियन डॉलर हो गया है।
- बाहरी क्षेत्र में अप्रैल 2020 में भारत के वस्तु व्यापार में निर्यात और आयात में क्रमशः 60.3% और 58.6% (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई है।
- इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण ईएमआई चुकाने से छूट को भी तीन महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु कॉयर जियो - टेक्सटाइल्स को मंजूरी

मई 2020 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (पीएमजीएसवाई-III) के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स के उपयोग को मंजूरी प्रदान की गई।

कॉयर जियो टेक्सटाइल्स: कॉयर जियो-टेक्स्टाइल एक ऐसी सामग्री है, जिसे नारियल रेशे से उच्च तन्यता मजबूती (high tensile strength) के साथ बनाया जाता है।

- यह एक पारगम्य फैब्रिक है तथा प्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ; टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी; व किसी भी सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) के हमले से मुक्त है।
- यह कम लागत पर मिट्टी को मजबूत करने में मदद करता है। जियो टेक्सटाइल का उपयोग ढलानों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य अनुप्रयोग सिविल इंजीनियरिंग उद्योग में हैं। इसका उपयोग एयरफील्ड्स, तटबंधों, जलाशयों, नहरों, बांधों, आदि में किया जाता है।

अन्य तथ्य: पीएमजीएसवाई -III के तहत 5% ग्रामीण सड़कों का निर्माण कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके किया जाएगा। तदनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके आंध्र प्रदेश, गुजरात केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में कुल 1674 किमी. सड़क का निर्माण किया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ पीएमजीएसवाई-III योजना को 2019 में मंजूरी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत राज्यों में 1,25,000 किमी. लंबी सड़कों को मजबूत बनाने की योजना है।

वर्तमान आर्थिक संकट के लिए शब्दावली

मई 2020 में दुनिया भर के अर्थशास्त्री 1929 की महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद आए वर्तमान सबसे बड़े आर्थिक संकट का वर्णन करने के लिए सही शब्दावली की खोज का प्रयास कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्व में आयरलैंड के सेंट्रल बैंक और कोविड-19 संकट के समय बीएनपी परिबास के लिए काम करने वाले अर्थशास्त्री डेविड मैकविलियम्स द्वारा इसके लिए 'पैनडेशन' (Pandession) नाम सुझाया गया है।

सुझाए गए अन्य नाम: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इसे 'ग्रेट लॉकडाउन' (Great Lockdown) कहा है। आईएमएफ ने इस वाक्यांश का उपयोग यह बताने के लिए किया कि विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे उलट-पलट हो गई।

- मॉर्गन स्टेनली ने इसे 'महा कोविड-19 मंदी' (Great Covid-19 Recession) कहा है, जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद से वैश्विक विकास में सबसे गहरे संकुचन की संभावनाओं को दर्शाता है।
- 1980 के दशक में 'बॉन्ड विजिलेंटेज' (Bond vigilantes) शब्द को गढ़ने वाले 'येर्डनी रिसर्च इंक' (Yardeni Research

Inc-) के अध्यक्ष और मुख्य निवेश रणनीतिकार एडेन वार्डेन ने इसे 'महान वायरस संकट' (Great virus crisis) नाम दिया है।

- 'ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' द्वारा इसे 'वैश्विक कोरोना वायरस मंदी' (Global Coronavirus Recession or GCR) नाम दिया गया है।
- ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों ने इस संकट के लिए 'ग्लोबल हार्ड स्टॉप' (Global Hard Stop) या 'वायरस मंदी' (Virus recession) जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया है।

सरकारी ऋण 2018–19 पर स्थिति पत्र

वित्त मंत्रालय ने 22 मई, 2020 को सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र (Status Paper) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज वित्त वर्ष 2017-18 में 45.8% से 0.1% कम होकर वित्त वर्ष 2018-19 में 45.7% हो गया।

- सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात, जिसमें केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण शामिल हैं, में भी 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो मार्च 2018 में 68.7% से मार्च 2019 में 68.6% हो गया है।
- वित्त वर्ष 2018-19 में बाहरी ऋण जीडीपी का 2.7% या 5.12 लाख करोड़ रुपये था। केंद्र की औसत ब्याज लागत वर्ष 2018 से 2019 तक 7.1% पर अपरिवर्तित रही। केंद्र की 94.1% देनदारियां घरेलू ऋण से सम्बंधित थीं।

सरकारी ऋण: सरकारी देनदारियों को सार्वजनिक खाते में देनदारियों (अन्य देनदारियों) और भारत के समेकित फंड के समक्ष अनुबंधित ऋण (सार्वजनिक ऋण) में वर्गीकृत किया गया है।

- सार्वजनिक ऋण को आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक ऋण में गैर-विपणन और विपणन योग्य ऋण शामिल हैं। बाहरी ऋण का तात्पर्य देश के बाहर के सभी स्रोतों से लिए गए ऋण से है।
- अन्य देनदारियों में भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ और जमा, अन्य खातों आदि के कारण देनदारियां शामिल हैं।

जीके फैक्ट

✧ वित्त मंत्रालय द्वारा 2010-11 से सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र जारी किया जा रहा है।

एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव

1 जून, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित आर्थिक पैकेज में एमएसएमई में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी।

- नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपये तक के निवेश और 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को 'सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाई' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 10 करोड़ रुपये तक के निवेश और 50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को 'लघु इकाइयों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 50 करोड़ रुपये के निवेश और 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाली एमएसएमई को 'मध्यम इकाइयों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अन्य तथ्य: संकटग्रस्त एमएसएमई को सहायक कर्ज के रूप में पूंजी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ रुपये तथा फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने को भी स्वीकृति दी गई।

जीके फैक्ट

✧ देश में 60 मिलियन से अधिक एमएसएमई हैं, जो भारत की जीडीपी में 29% का योगदान करते हैं।

भारतमार्केट

मई 2020 में व्यापारियों के संगठन 'अखिल भारतीय व्यापारी संघ' (Confederation of All India Traders- CAIT) ने शीघ्र ही राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस 'भारतमार्केट' लांच करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: कई प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ मिलकर तैयार किया गया यह प्लेटफार्म विशेष रूप से देशभर के खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है।

- भारतमार्केट निर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक होम डिलीवारी सहित लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा।
- ई-कॉमर्स पोर्टल पर 95 प्रतिशत खुदरा व्यापारियों को एक मंच प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- CAIT ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर 2020 में लगभग एक करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ने की योजना बना रहा है। खुदरा व्यापारी मार्केटप्लेस में शेयरधारक होंगे और पोर्टल विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ CAIT राष्ट्रीय स्तर पर भारत के व्यापारिक समुदाय का एक सर्वोच्च निकाय है। 1990 में व्यापारियों की समस्याओं के प्रबंधन के लिए इस फोरम का गठन किया गया।

द सरस कलेक्शन

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 मई, 2020 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर 'द सरस कलेक्शन' (The Saras collection) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'द सरस कलेक्शन' सरकारी ई-मार्केटप्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है।

- यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है।
- इस पहल के तहत, एसएचजी विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों (i) हस्तशिल्प, (ii) हथकरघा और वस्त्र, (iii) कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सामान, (iv) किराना और पेंट्री, और (v) व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई में सूचीबद्ध कर सकेंगे।

जीके फैक्ट

- ✧ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना और आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है।
- ✧ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था तथा 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई, 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस बैठक में वर्तमान वैश्विक एवं घरेलू वृहद-आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता तथा कमजोरी से जुड़े मुद्दों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष उभरने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की गई।

- इसके अलावा बाजार में अस्थिरता, घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चाएं की गईं।

वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद: यह भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च निकाय है। इस परिषद की स्थापना 2010 में की गई थी।

- वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इस परिषद् में RBI के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के सचिव; SEBI, IRDA, PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) और IBBI के चेयरमैन शामिल होते हैं।
- यह परिषद वित्तीय क्षेत्र के विकास, वित्तीय स्थिरता, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता जैसे मुद्दों से संबंधित है।

जीके फैक्ट

- ✧ 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद के गठन की अनुशंसा की गई थी।

एनबीएफसी/एचएफसी हेतु विशेष नकदी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की नकदी की समस्या के समाधान के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी योजना को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: दबाव परिसंपत्ति कोष (एसएएफ) के प्रबंधन के लिए एक विशेष कंपनी (एसपीवी) बनाई जाएगी, जिसकी विशेष प्रतिभूतियों पर सरकार गारंटी देगी और इनकी खरीद रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी।

- एसपीवी जरूरत के हिसाब से प्रतिभूतियां जारी करेगा, जो प्रतिभूतियों की बकाया राशि पर निर्भर करेगा और यह राशि 30,000 करोड़ से अधिक नहीं होगी।
- एसपीवी द्वारा इस तरह की प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल एनबीएफसी-एचएफसी के लघु अवधि के ऋण-पत्र खरीदने के लिए किया जाएगा। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत होगी।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा योजना के कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा ऋणदात्री संस्थाओं बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी।

- इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत ऋण की अवधि 4 साल होगी और इसकी अधिस्थगन अवधि (Moratorium period) मूलधन पर एक साल होगी।
- गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा योजना के तहत वे सभी एमएसएमई योग्य होंगे, जिनका बकाया ऋण 29 फरवरी, 2020 को 25 करोड़ रुपये तक और जिनका 100 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार हो।
- योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25 फीसदी और गैर- वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकतम 14 फीसदी होगी।
- यह योजना GECL के तहत 31 अक्टूबर, 2020 तक स्वीकृत सभी ऋणों या 3 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पर लागू होगी। ■■

राष्ट्रीय

भारत में टिड्डियों का खतरा

मई 2020 में फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) के शहरी क्षेत्रों में देखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: 11 अप्रैल को भारत-पाकिस्तान सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में टिड्डियों के दल को पहली बार देखा गया था। आमतौर पर जुलाई-अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं।

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, टिड्डियां भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहीं हैं।

टिड्डियां: दुनिया भर में टिड्डियों की 10 हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल चार प्रजाति ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और पेड़ वाली टिड्डी शामिल हैं।

- एक वयस्क मादा टिड्डी अपने तीन महीने के जीवन चक्र में तीन बार 80-90 अंडे देती है। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो एक टिड्डी दल प्रति वर्ग किमी. 40-80 मिलियन टिड्डी तक तेजी से बढ़ सकता है, जिससे ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

टिड्डियों के पूर्वागमन का कारण: टिड्डियों के पूर्वागमन का प्रमुख कारण मई और अक्टूबर 2018 में आए मेकुनु और लुबान नामक चक्रवाती तूफान हैं, जिनके कारण दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे। जिससे भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ।

जीके फैक्ट

✧ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine - Storage) के अधीन 'टिड्डी चेतावनी संगठन' का मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी।

स्टाइरीन गैस रिसाव

7 मई, 2020 को विशाखापत्तनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस कंपनी के संयंत्र से स्टाइरीन गैस के रिसाव होने के कारण 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। दुर्घटना से संयंत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के लोग प्रभावित हुए।

- आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की।

स्टाइरीन: स्टाइरीन (C_8H_8) एक जहरीला ज्वलनशील तरल है तथा यह बेंजीन का व्युत्पन्न है। इसे एक तरल के रूप में कारखानों में संग्रहीत किया जाता है, लेकिन यह आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना पड़ता है।

- इसका उपयोग पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है।

रिसाव का कारण: कंपनी के अनुसार भंडारण टैंक के अंदर तापमान में ठहराव और परिवर्तन होने के कारण स्व-बहुलकीकरण (auto polymerization) के परिणामस्वरूप वाष्पीकरण रिसाव का कारण हो सकता है।

प्रभाव: इसके अल्पकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों तथा श्लेष्म झिल्ली में जलन और जठरांत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और दीर्घकालिक जोखिम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को काफी प्रभावित कर सकता है।

जीके फैक्ट

✧ वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टाइरीन और इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की थी। वर्ष 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केमिकल ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया और इसका नाम परिवर्तित कर 'एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया गया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: कुल 20050 करोड रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना, केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी।

- इसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 9407 करोड रूपए, राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5763 करोड रुपए होगी।

- इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।
- केंद्र प्रायोजित योजना घटक को गैर-लाभार्थी केन्द्रित और लाभार्थी केन्द्रित गतिविधियों में तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है- 'उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन', 'अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन' तथा 'मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क'।

वित्तपोषण: केन्द्रीय परियोजना के लिए 100% वित्तीय सहायता केन्द्र की ओर से की जाएगी।

- राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले केंद्र प्रायोजित योजना घटक केलिए संपूर्ण परियोजना लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाएगी। जिसमें पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य के लिए (केंद्र 90% तथा राज्य 10%) अन्य राज्य के लिए (केंद्र 60% तथा राज्य 40%) तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए (100% केंद्र) योगदान करेंगे।
- लाभार्थी केंद्रित अर्थात व्यक्तिगत/सामूहिक गतिविधियों के लिए सामान्य श्रेणी वाली परियोजना में केंद्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेशों की कुल हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगी तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़ी परियोजना के लिए 60 प्रतिशत की आर्थिक मदद दी जाएगी।

पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा 3100 करोड़ रुपए आवंटित

पीएम केयर्स (प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन्स) फंड ट्रस्ट ने 13 मई, 2020 को कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए 3100 करोड़ रुपये का आवंटन करने का फैसला लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें से बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पीएम केयर्स फंड से लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 50000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर्स की खरीद की जाएगी।

- ये वेंटिलेटर्स कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए समस्त राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड अस्पतालों को प्रदान किए जाएंगे।
- प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों को पीएम केयर्स फंड से कुल 1000 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि जिला कलेक्टर/जिला मेजिस्ट्रेट/नगर आयुक्तों को संबंधित राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों के राज्य आपदा राहत आयुक्त के माध्यम से जारी की जाएगी।
- इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन को डिजाइन और विकसित करने वालों की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में किया जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ 27 मार्च, 2020 को गठित पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और ट्रस्ट के अन्य पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई, 2020 को 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना' (Defence Testing Infrastructure Scheme- DTIS) को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु, इस क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना तैयार करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ छः से आठ नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

- इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप सैन्य उपकरणों का आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में 75% तक धन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना की लागत का शेष 25% विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी।
- इस योजना के अंतर्गत, एसपीवी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और वह उपयोगकर्ता शुल्क एकत्रित करके इस योजना के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का स्व-संधारणीय तरीके से संचालन और रखरखाव भी करेगा।
- अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) में ही समाहित करने की संभावना है, लेकिन इस योजना को केवल डीआईसी में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रखा गया है।

ढांचागत संरचना निर्माण संबंधित शेकातकर समिति सिफारिश लागू

मई 2020 में सरकार ने सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकातकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित मामले पर सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की अधिकतम क्षमता से अतिरिक्त सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स करने के लिए समिति की सिफारिश को लागू किया है।

- 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के

निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (ईपीसी) मोड को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

- आधुनिक निर्माण संयंत्रों की स्थापना करने और उपकरणों व मशीनरी की खरीद करने से सम्बंधित दूसरी सिफारिश को लागू करते हुए बीआरओ की खरीद क्षमता को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- बीआरओ घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की खरीद कर सकती है।
- परियोजना की शुरूआत से पहले पूर्व मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित समिति की सिफारिश को लागू करते हुए भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी वैधानिक स्वीकृति को भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मंजूरी का हिस्सा बनाया गया है।

जीके फैक्ट

✧ शेकातकर समिति का गठन 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा किया गया था।

कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 मई, 2020 को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की।

उद्देश्य: कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए शहरों के तंत्र को संस्थागत रूप देना और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए शहरों को प्रेरित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए कुल 141 शहरों को रेटिंग दी गई - उनमें से 6 शहरों को '5-स्टार', 65 शहरों को '3-स्टार' तथा 70 शहरों को '1-स्टार' रेटिंग दी गई। स्टार रेटिंग मूल्यांकन के इस चरण में 1435 शहरों ने आवेदन किया था।

- 5-स्टार रेटिंग वाले शहरों में शामिल हैं-अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), राजकोट (गुजरात), सूरत (गुजरात), मैसूरु (कर्नाटक), इंदौर (मध्य प्रदेश) और नवी मुंबई (महाराष्ट्र)।
- करनाल, नई दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई नगर, अहमदाबाद '3-स्टार' कचरा मुक्त रेटिंग में शामिल हैं, जबकि दिल्ली छावनी, वडोदरा, रोहतक '1-स्टार' कचरा मुक्त शहरों में से हैं। किसी भी शहर को '7-स्टार' रेटिंग हासिल नहीं हुई।

जीके फैक्ट

✧ जनवरी 2018 में 'स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल' लॉन्च किया गया था, जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और तोड़ दिए गए भवनों के अपशिष्ट आदि शामिल हैं। इसके तहत हर शहर में प्रत्येक वार्ड को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के 24 अलग-अलग घटकों में एक निश्चित मानक प्राप्त करना होता है।

भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली 'मेड इन इंडिया' इंजन

भारतीय रेलवे ने 18 मई, 2020 को 12000 हॉर्स पावर (एचपी) का अपना सबसे शक्तिशाली 'मेड इन इंडिया' इंजन सफलतापूर्वक चलाया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस रेलवे इंजन का नाम 'डब्ल्यूएजी12बी' (WAG12B) है तथा इसने उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक दौड़ लगाई।

- भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है।
- पूरी दुनिया में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है।
- ये उच्च हॉर्स पावर वाले इंजन मालवाहक ट्रेनों की औसत गति और लदान क्षमता बढ़ाकर अत्यधिक इस्तेमाल वाली पटरियों पर भीड़ कम करने में मदद करेंगे।
- यह इंजन 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत फ्रांस की कंपनी आल्सटॉम द्वारा मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (एमईएलपीएल) में निर्मित किया गया है।
- 120 इंजनों (लोकोमोटिव) की उत्पादन क्षमता वाला मधेपुरा कारखाना गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ तैयार की गई सबसे बड़ी एकीकृत नई (ग्रीनफील्ड) यूनिट है।

जीके फैक्ट

✧ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अप्रैल, 2018 को इस परियोजना का उदघाटन किया गया था।

पीएम स्व-निधि योजना

1 जून, 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना 'पीएम स्व-निधि' (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PMSVANidhi) शुरू की है।

उद्देश्य: कोविड-19 संकट के मद्देनजर रेहड़ी विक्रेताओं को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए सस्ती क्रेडिट सुविधा प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: योजना के तहत रेहड़ी विक्रेता 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।

- ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छः माह के आधार पर जमा की जाएगी।
- इस योजना को संचालित करने के लिए वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप को क्रेडिट प्रबंधन

के लिए सिडबी के 'उद्यमी मित्र' पोर्टल और ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से प्रबंधित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 'पैसा' (PAiSA) पोर्टल के साथ एकीकृत करेगा।

- विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को 10,000 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित 'सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना' को स्वीकृति प्रदान की।

उद्देश्य: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त की पहुँच में वृद्धि; खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन; असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन; जनजातीय जिलों में लघु वन उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: योजना के व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।

- योजना को 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। इसके तहत 2,00,000 सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- 10 लाख रुपए तक की लागत वाली वैध परियोजना के सूक्ष्म उद्यमों को 35% की दर से ऋण से जुड़ी सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना की निगरानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा केन्द स्तर पर की जाएगी। योजना की सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर संचालित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि: देश में करीब 25 लाख अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, जो इस क्षेत्र का 98% है और ये असंगठित और अनियमित हैं। इनमें से 66% इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस क्षेत्र को बहुत सी चुनौतियों जैसे ऋण तक पहुँच न होना तथा संस्थागत ऋणों की ऊँची लागत आदि का सामना करना पड़ता है।

प्रभाव: इस परियोजना से नौ लाख कुशल और अल्प-कुशल रोजगारों के सृजन की संभावना है।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' में शामिल पांच नए राज्य/ संघ-शासित क्षेत्र

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने 1 जून, 2020 को 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ तीन राज्यों को जोड़ने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये 3 नए राज्य हैं- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या अब 20 हो गई है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 17 राज्य/ संघ शासित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं।

- लाभार्थी इन 20 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान से अपने हक का राशन खरीद सकते हैं।
- राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की प्रायोगिक योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों यानी 83% पीडीएस आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा।

जीके फैक्ट

- 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) को तीन साल की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा योजना मार्च 2023 तक मान्य होगी।

- सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रतिफल दर (annual rate of return) 7.4% तय किया है तथा इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित किया जाएगा।
- 2017 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) हर महीने वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। पॉलिसी का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित है।
- इसमें न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह तथा अधिकतम 10000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

जीके फैक्ट

- योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है।

अटल पेंशन योजना के पांच वर्ष

9 मई, 2020 को भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना 'अटल पेंशन योजना' (एपीवाई) ने सफल कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर लिए हैं।

उद्देश्य: विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देना और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना की शुरूआत 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी।

- इन पांच वर्षों में एपीवाई की यात्रा अभूतपूर्व रही है और 9 मई 2020 तक, इस योजना के तहत कुल 2.23 करोड़ श्रमिकों के नाम दर्ज किए गए हैं।
- इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र- शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और इसमें पुरुष के साथ महिला सदस्यता अनुपात 57:43 है।

अटल पेंशन योजना: एपीवाई का लाभ 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है, जिसके पास बैंक खाता है।

- यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है।
- ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि दी जाती है तथा ग्राहक और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान की जाती है।

जीके फैक्ट

✧ अटल पेंशन योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।

ईआरपी 'समर्थ'

मई 2020 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कुरूक्षेत्र में उद्यम संसाधन योजना-ईआरपी (Enterprise Resource Planning-ERP) 'समर्थ' को कार्यान्वित किया गया है।

उद्देश्य: संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'सूचना और प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (National Mission of Education in Information and Communication Technology Scheme- NMEICT) के तहत विकसित किया गया है।



- ईआरपी 'समर्थ' विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक मानक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, मजबूत, सुरक्षित, विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र (Evolutionary Process Automation Engine) है।
- यह विश्वविद्यालय/उच्च शैक्षिक संस्थानों में संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- ईआरपी 'समर्थ' को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' (Technical Education Quality Improvement Program- TEQIP) के तहत हिस्सा लेने वाली इकाई है।
- ईआरपी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग संस्थान/संगठन दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए करते हैं।

जीके फैक्ट

✧ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2002 में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' शुरू किया था।

कोणार्क शत-प्रतिशत सौरीयन योजना

मई 2020 में भारत सरकार ने ओडिशा में 'कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के शत प्रतिशत सौरीयन की योजना' (scheme for 100 per cent solarisation of Konark sun temple and Konark town) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: ऊर्जा के आधुनिक उपयोग तथा प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल के संदेश को प्रकट करना तथा सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को 'सूर्य नगरी' के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में लगभग 25 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी।

- 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विविध सौर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर वृक्ष (Solar Tree), सौर पेयजल कियोस्क (Solar drinking water kiosks), बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना आदि की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

सौर वृक्ष: सौर वृक्ष दिखने में सामान्य वृक्ष जैसे ही होते हैं, जिसमें शाखाओं के रूप में सौर पैनल लगे होते हैं तथा ये धातु संरचना से बने होते हैं।

जीके फैक्ट

✧ पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।

कार्यक्रम 'गोल'

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मई, 2020 को फेसबुक के सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम 'गोल' (Going Online As Leaders-GOAL) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: भारत में जनजातीय स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या में वृद्धि करना तथा जनजातीय समुदाय के भीतर रोल मॉडल तैयार करना, जो आगे चलकर प्रेरणा स्रोत बन सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'गोल' फेसबुक और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मेंटरशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कौशल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

- इस कार्यक्रम के तहत 5,000 युवा आदिवासी उद्यमियों, पेशेवरों, कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- चयनित युवा आदिवासियों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्धता (एक वर्ष के लिए) के साथ-साथ विभिन्न बाहरी फोरमों तक संपर्क प्रदान किया जाएगा।
- 'गोल' कार्यक्रम आदिवासी उद्यमिता को विकसित कर आदिवासी युवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ेगा।
- फेसबुक द्वारा स्वयं इस परियोजना को फरवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक 5 राज्यों में 100 'मेंटीज' (Mentees) (युवा आदिवासियों) और 25 (विशेषज्ञों) मेंटर्स के साथ पायलट परियोजना के रूप में चलाया गया था।

नए भौगोलिक संकेतक टैग

12 मई, 2020 को झारखंड की 'सोहराई खोवर पेंटिंग' और तेलंगाना के 'तेलिया रुमाल' तथा तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित 'तंजावुर नेति वर्क्स' (Thanjavur Netti Works) और 'अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी' को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया।

सोहराई खोवर पेंटिंग: यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग कर फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है।

- इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चिन्हित किया जाता था, किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चिन्हित किया जाता है, जिसमें रेखाओं, विन्दुओं, जानवरों के चित्र एवं पेड़-पौधों का चित्रण किया जाता है।

तेलिया रुमाल: तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें तीन विशेष रंगों लाल, काला और सफेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है।

तंजावुर नेति वर्क्स: यह एक पारंपरिक कला है, जो एक दलदली पादप 'एशिनोमेन एस्पेरा' (Aeschynomene Aspera) के नेति (डंठल के भीतरी भाग) से तैयार किया जाता है। नेति वर्क्स व्यापक रूप से बृहदेश्वर मंदिर, हिंदू मूर्तियों, मालाओं, दरवाजों और सजावट में पाए जाते हैं।

अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी: पेरम्बलुर जिले के कारीगरों द्वारा अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से आम, शीशम, नीम के पेड़ की लकड़ी के लट्ठे (Wooden logs) से तैयार की जाती है। ये नक्काशी अक्सर मंदिर की मूर्तियों और नक्काशियों पर वास्तुशिल्प विवरण से प्रेरित होती है।

नई संसद परियोजना को मंजूरी

अप्रैल 2020 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 922 करोड़ रुपये के नए संसद भवन निर्माण के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के अनुसार, संसद का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और एक नई इमारत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य त्रिकोणीय संसद भवन बनाना है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किमी. लंबे राज पथ की मरम्मत की जायेगी।

- सेंट्रल विस्टा क्या है? नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार हैं।
- संसद भवन को लुटियन्स और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन्स द्वारा डिजाइन किया गया था और सचिवालय में उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं, जिसे हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था।

लाभ: यह परियोजना 2022 तक पूरी हो जाएगी। नई इमारतों में भूमिगत पार्किंग व्यवस्था होगी। साथ ही, नए भवन में मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी।

अंतरराष्ट्रीय

भारत–ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन

4 जून, 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच पहला भारत - ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।



महत्वपूर्ण तथ्य: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' की घोषणा की। दोनों देशों ने 'हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र' भी जारी किया है।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी: इसके तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, कृषि सहयोग और जल संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय निकायों में समर्थन, लोक प्रशासन और गवर्नेंस में सहयोग शामिल है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग: भारत और ऑस्ट्रेलिया सभी इच्छुक भागीदारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में घोषित हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI) विकसित करने के लिए निकटता से काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से, वे साझा समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करेंगे।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन' (UNCLOS) पर आधारित है।

समझौते: दोनों देशों के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग, खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग, परस्पर लॉजिस्टिक सहयोग समझौता, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग पर समझौते शामिल हैं।

जी–7 शिखर सम्मेलन स्थगित

30 मई, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जून में आयोजित होने वाले 'जी-7 शिखर सम्मेलन' को सितंबर तक स्थगित करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमेरिकी राष्ट्रपति ने जी-7 को जी-10 या जी-11 तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है।

- उन्होंने विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह में भारत और तीन अन्य राष्ट्रों रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की योजना बनाई है।
- ट्रम्प के अनुसार जी-7 विश्व का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह देशों का बहुत पुराना समूह है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दूरभाष से बातचीत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस साल जी-7 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है।
- वर्तमान में जी-7 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम हैं। इन देशों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा के मुद्दों पर हर साल बैठक करते हैं।

जीके फैक्ट

- जी-7 एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 1975 में हुआ था। कनाडा 1976 में जी-7 में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ 1977 से जी-7 की बैठक में भाग लेने लगा।
- 1997 में रूस जी-7 में शामिल हुआ। शुरू में जी-7 को जी-8 कहा जाता था। 2014 में रूस को यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करने के कारण इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था।

73 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020

18-19 मई, 2020 को 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे (कोविड-19 महामारी) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया।

- इस वर्ष की विश्व स्वास्थ्य महासभा में WHO की महामारी की प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच करने का आह्वान किया गया।

अब तक भारत, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 122 देशों ने इसका समर्थन किया है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस ने समीक्षा का समर्थन किया और कहा कि डब्ल्यूएचओ पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
- 22 मई को, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र के दौरान अध्यक्ष पद संभाला।
- वे 2020-21 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जापान के डॉ. हिरोकी नकातानी का स्थान लिया।

जीके फैक्ट

✧ विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ की निर्णय लेने वाली संस्था है। यह संगठन की नीतियों का निर्धारण करने, महानिदेशक की नियुक्ति करने तथा प्रस्तावित बजट कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है।

कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल

29 मई, 2020 को कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' (COVID-19 Technology Access Pool- C-TAP) लॉन्च किया है।

उद्देश्य: खुले विज्ञान अनुसंधान (open-science research) के माध्यम से कोविड-19 के उपचार में मदद हेतु टीकों, परीक्षण, दवाओं और अन्य प्रौद्योगिकियों की खोज में तेजी लाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: C-TAP वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए एक केंद्रक के रूप में कार्य करेगा।

- मजबूत विज्ञान और सहयोग के आधार पर, यह सूचना-साझाकरण प्लेटफॉर्म दुनिया भर में जीवन-रक्षक प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।
- लगभग 30 देशों, संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने C-TAP का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

पूल के पांच प्रमुख तत्व: जीन अनुक्रमों और डाटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण; सभी नैदानिक परीक्षण परिणामों के प्रकाशन में पारदर्शिता; सरकारों और अन्य फंड का प्रबंधन करने वालों को दवा कंपनियों और अन्य नवोन्मेषकों के साथ धन समझौतों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना; संभावित उपचार, नैदानिक, टीके या अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की लाइसेंसिंग; तथा अभिनव मॉडल को बढ़ावा देना।

जीके फैक्ट

✧ 'कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' पहल कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तावित की गयी थी।

लिपुलेख – कालापानी विवाद

19 मई, 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के क्षेत्र शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: ज्ञात हो कि, भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें लिपुलेख और कालापानी को शामिल किया गया था।

- 'लिपुलेख दर्रा' नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमावर्ती क्षेत्र कालापानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है।
- भारत और नेपाल दोनों 'कालापानी' को अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं - भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में। यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें उच्च हिमालय में कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

सुगौली संधि: नया मानचित्र नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश-भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 1816 की सुगौली संधि के आधार पर तैयार किया गया है।

- इस संधि के अनुसार, ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी। नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार, काली नदी का पूर्व भाग नदी के स्रोत पर शुरू होना चाहिए। उनके अनुसार स्रोत लिम्पियाधुरा के पास पहाड़ों में है।
- दूसरी ओर भारत का दावा है कि सीमा कालापानी में शुरू होती है, जहां से नदी शुरू होती है।
- नेपाल संसद द्वारा भारतीय क्षेत्र के हिस्सों पर दावा करने वाले देश के अद्यतन नक्शे को कानूनी दर्जा देने के लिए 'दूसरा संविधान संशोधन विधेयक' पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गयी है।

जीके फैक्ट

✧ देश के अद्यतन नक्शे को कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक को 31 मई को संसद में नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवा माया तुंबाहांगफे ने पेश किया था।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई, 2020 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 (Energy Transition Index 2020) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

- उसके पश्चात स्विट्जरलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा तथा नॉर्वे को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है।
- सूचकांक में शीर्ष दस में मात्र दो जी-20 समूह के देश हैं। फ्रांस (8वें स्थान पर) और यूनाइटेड किंगडम (7वें स्थान पर)।

- इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत 76वें तथा वर्ष 2018 में 78वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 55वें, चीन 78वें, बांग्लादेश 87वें, पाकिस्तान 94वें, नेपाल 95वें स्थान पर है। सूचकांक में अंतिम 115वें स्थान पर हैती है।
- यह सूचकांक इन देशों के उर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है।
- भारत द्वारा ऊर्जा त्रिभुज के सभी तीन आयामों में सुधार हुआ है - आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा तक पहुंच और सुरक्षा और पर्यावरणीय संधारणीयता।

जीके फैक्ट

✧ ब्रिक्स देशों में ब्राजील 47वें, रूस 80वें तथा दक्षिण अफ्रीका 106वें स्थान पर है।

भारत और भूटान के बीच पर्यावरण सहयोग पर समझौता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2020 को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह समझौता ज्ञापन दोनों देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

- समझौता ज्ञापन में वायु, अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और यह हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 वर्षों तक लागू रहेगा।
- समझौता ज्ञापन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों और तकनीकी जानकारियों को आदान-प्रदान करने के साथ-साथ सतत विकास में योगदान देगा।

जीके फैक्ट

✧ दोनों देशों के बीच पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग पर 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन 2016 में समाप्त हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने का निर्णय लिया है।

ओपन स्काइज संधि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 21 मई, 2020 को घोषणा की कि अमेरिका अब ओपन स्काइज संधि से अलग हो जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संधि से पीछे हटने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि रूस ने इस संधि की अवहेलना की है।

- डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह ऐसा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिका अलग हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौता से अलग होने का फैसला किया था।
- ओपन स्काइज संधि पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा 2002 में यह संधि लागू हुई। इस संधि के तहत सदस्य देशों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है।
- 34 सदस्य देशों के इस संधि पर हस्ताक्षर हैं। अमेरिका और रूस दोनों संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। किर्गिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है।
- ओपन स्काइज संधि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश को सैन्य बलों और गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने के लिए दूसरे सदस्य देश के संपूर्ण क्षेत्रों पर शॉर्ट-नोटिस पर निहत्थे, हवाई अवलोकन की अनुमति देती है।

जीके फैक्ट

✧ भारत की जापान के साथ भी ऐसी ही संधि है। भारत और जापान ने 2017 में 'ओपन स्काई' समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यूरोपीय संघ का कोविड-19 रिकवरी फंड

27 मई, 2020 को यूरोपीय संघ ने 750 बिलियन यूरो का कोविड-19 रिकवरी फंड प्रस्तावित किया। इस कोष का उपयोग सदस्य देशों द्वारा कोविड-19 के कारण होने वाली गहरी मंदी से उबरने हेतु किया जायेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रस्ताव के तहत, अभूतपूर्व मंदी को दूर करने के लिए यूरोपीय आयोग बाजार से धन उधार लेगा और फिर दो-तिहाई अनुदान और शेष ऋण में वितरित करेगा।

- अधिकांश पैसा महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपीय संघ के देश इटली और स्पेन में जाएगा।
- फ्रांस और जर्मनी ने पहले समूह के वित्तीय उपायों के लिए नकदी जोड़ने के लिए 500 बिलियन यूरो (543 बिलियन डॉलर) का फंड देने पर सहमति व्यक्त की थी। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, और नीदरलैंड किसी भी विशेष मांग या सीमा को निर्धारित किये बिना धन देने के संबंध में अनिच्छुक रहे हैं।
- यूरोपीय संघ फ्रेंको-जर्मन मॉडल के समान कई प्रकार के ब्लूप्रिंट लागू करेगा।

फ्रेंको-जर्मन मॉडल: भारत सहित लगभग 25 देशों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कोरोना वायरस को रोकने के तरीकों हेतु इस मॉडल का समर्थन किया है। इस गठबंधन का नेतृत्व फ्रांस और जर्मनी द्वारा किया गया था और यह मॉडल 25 देशों की बैठक का एक परिणाम है, जो अप्रैल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गयी थी।

- इस मॉडल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को परीक्षणों और टीकों को विकसित और वितरित करने के लिए मजबूत करना है।

चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने संबंधित विधेयक

अमेरिकी सीनेट ने 20 मई, 2020 को सर्वसम्मत मत से एक विधेयक पारित किया, जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर बेचने से रोक सकता है।

उद्देश्य: अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवानिवृत्ति बचत को विदेशी कंपनियों से बचाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट' (Holding Foreign Companies Accountable Act) शीर्षक वाले इस विधेयक को रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वान होलेन द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया। यह विधेयक अब प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा।

- यदि कोई कंपनी 'सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड' (PCAOB) के साथ लगातार तीन साल तक ऑडिट का पालन करने में विफल रहती है, तो विधेयक किसी भी अमेरिकी प्रतिभूति एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित करता है।
- नए विधेयक में सार्वजनिक कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहित किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या नहीं।
- यह विधेयक सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन इसका प्रमुख निशाना चीनी कंपनियाँ हैं। चीनी कंपनियों ने अमेरिकी रिपोर्टिंग मानकों की अवहेलना की है और अपने निवेशकों को बहुत लंबे समय तक गुमराह किया है।

प्रभाव: सीनेट में यह विधेयक पारित होने के बाद, चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा के शेयरों में अमेरिका के सूचीबद्ध शेयरों से 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई।

वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020

4 जून, 2020 को ब्रिटेन के नेतृत्व में वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सम्मेलन में 50 से अधिक देशों - व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने भाग लिया।



- दुनिया भर की सरकारों ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन 'गावी' के लिए 8.8 बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता की, ताकि कोरोनवायरस द्वारा बाधित टीकाकरण कार्यक्रमों में मदद मिल सके।
- भारत ने भी गावी को 15 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता की है। ज्ञात हो कि यह शिखर सम्मेलन गावी के लिए कम से कम 7.4 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया गया था।
- ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है।

जीके फैक्ट

✧ वैक्सीन गठबंधन 'गावी' वर्ष 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियों, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया था। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना तथा देशों को सतत विकास लक्ष्यों के करीब लाना है।

चीन द्वारा हांगकांग संबंधित विवादास्पद कानून पारित

चीन की संसद द्वारा 28 मई, 2020 को हांगकांग के लिए नया कानून पारित किया, जो पहली बार बीजिंग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए सशक्त करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाए गए नए मसौदा विधेयक का उद्देश्य हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के लिए कानूनी प्रणाली और प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना है।

- इसके अनुसार कानूनों का दायरा ऐसी किसी भी गतिविधि को कवर कर सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालती है।
- इसका उद्देश्य अलगाववादियों, विध्वंसक, घुसपैठ या विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हांगकांग के विदेशी और विदेशी ताकतों के उपयोग को रोकने, कानूनी रूप से रोकने और दंडित करने के उपायों को सक्षम करना है।

मूलभूत कानून: पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, हांगकांग को 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया था, जो इसका 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों' में से एक है। यह 'मूलभूत कानून' (Basic law) नामक एक मिनी-संविधान द्वारा शासित है, जो 'एक राष्ट्र, दो व्यवस्था' के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

प्रतिक्रिया: इस कानून के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन के इस फैसले पर चिंता जताई है और कानून संशोधन की प्रक्रिया तत्काल रोकने को कहा है। उन्होंने प्रस्तावित कानून को 'एक राष्ट्र, दो व्यवस्था' के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। ■■

विज्ञान–पर्यावरण

'नगर वन' विकसित करने की शहरी वन योजना

5 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग से अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए 'नगर वन योजना' के कार्यान्वयन की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए देश भर में 200 नगर पालिकाएं और नगर निगम योजनाएं विकसित करेंगे। यह पहल 2015 में शुरू की गई वरजे, पुणे के 'स्मृति वन मॉडल' पर आधारित है, जिसमें महाराष्ट्र के वन विभाग और स्थानीय निकाय ने पुणे में 16.8 हेक्टेयर बंजर पहाड़ी को हरे वनों में परिवर्तित कर दिया था।

- शहरी वनों में पूरे शहर तथा पेड़ों और संबंधित जीवों, संरचनाओं और लोगों का वातावरण शामिल होता है।

लाभ: शहरी वानिकी के आर्थिक से लेकर पारिस्थितिक तक असंख्य लाभ हैं। इसके पारिस्थितिक लाभों में शहरी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि में कमी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, अन्य वायु प्रदूषकों को हटाना, मिट्टी के कटाव को रोकना, भूजल का पुनर्भरण और मृदा का स्थिरीकरण शामिल हैं।

जीके फैक्ट

✧ विश्व पर्यावरण दिवस 2010 का विषय (theme) 'जैव-विविधता' है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020

येल विश्वविद्यालय द्वारा 4 जून, 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सूचकांक के 12वें संस्करण में 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा गया। यह सूचकांक द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है।

- सूचकांक ने रैंकिंग हेतु पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर पर्यावरण के प्रदर्शन में 10 साल के रुझानों का अवलोकन था।
- डेनमार्क 100 में से 82.5 स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है। उसके बाद लक्जमबर्ग दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे, यूनाइटेड किंगडम चौथे तथा फ्रांस पांचवें स्थान पर है। सूचकांक में सबसे नीचे लाइबेरिया 180वें तथा म्यांमार 179वें स्थान पर हैं।

भारत की स्थिति: इस सूचकांक में भारत को 27.6 स्कोर के साथ 168वां स्थान हासिल हुआ। वर्ष 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान 177वां था।

- अफगानिस्तान (178वें स्थान) को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश रैंकिंग में भारत से आगे रहे। भूटान 107वें, श्रीलंका 109वें, मालदीव 127वें, पाकिस्तान 142वें, नेपाल 145वें तथा बांग्लादेश 162वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय संधारणीयता प्रयासों (National sustainability efforts) को फिर से दोगुना करने की आवश्यकता है। विशेषकर वायु और जल गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे संधारणीयता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

जीके फैक्ट

✧ जैव विविधता और आवास में भारत दुनिया में 148वें स्थान पर रहा, जबकि जलवायु परिवर्तन शमन में 106वें स्थान पर है।

आईएनएलसीयू एल57

अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. राजेश्वर ने 15 मई, 2020 को पोर्ट ब्लेयर में 'आईएनएलसीयू एल57' (INLCU L57) को भारतीय नौसेना में सेवा के लिए शामिल/कमीशन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 'आईएनएलसीयू एल57' लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एमके-IV (Landing Craft Utility MK-IV) श्रेणी का सातवाँ पोत है।

- इस पोत को मैसर्स 'गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा स्वदेशीय रूप से डिजाइन औरनिर्मित किया गया है।



- एलसीयू एमके-IV पोत एक जल तथा स्थल पर कार्य करने योग्य पोत है, जिसे मुख्य युद्धक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को पोत से तट पर ले जाने और तैनात करने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है।
- अंडमान एवं निकोबार कमान में स्थित इन पोतों को तटीय अभियान, खोज व बचाव, आपदा राहत अभियान, आपूर्ति तथा दूरस्थ द्वीपों से निकासी जैसी विविध गतिविधियों के लिए तैनात किया जा सकता है।
- यह पोत 830 टन विस्थापन के साथ विभिन्न प्रकार के युद्धक उपकरणों जैसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, टी72 और अन्य वाहनों को ले जाने में सक्षम है।
- यह पोत अत्याधुनिक उपकरण और उन्नत प्रणालियों, जैसे इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)और इंटीग्रेटेड प्लैटफॉर्म मेनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) से लैस है।

जीके फैक्ट

✧ एलसीयू एमके-IV का पहला पोत 'आईएनएलसीयू एल51' मार्च 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था।

बीएस–6 के लिए L7 श्रेणी हेतु उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित

24 मई, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज मानक (बीएस-6) के लिए L7 (क्वाड्रिसाइकल) श्रेणी के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अधिसूचित किया।



महत्वपूर्ण तथ्य: इस अधिसूचना के साथ, देश में बीएस-6 प्रक्रिया सभी एल, एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए पूरी हो गई।

- 2018 में सरकार ने वाहन के उत्पादन के लिए आवश्यक मानकों के साथ क्वाड्रिसाइकल सेगमेंट को पेश किया था। इसने वाणिज्यिक और निजी उपयोग दोनों के लिए वाहन को मंजूरी दी थी।

क्वाड्रिसाइकल क्या है? क्वाड्रिसाइकल एक ऐसा वाहन है, जो थ्री व्हीलर के आकार का होता है लेकिन चार पहियों से चलता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत क्वाड्रिसाइकल को 'गैर-परिवहन' के वाहन के अंतर्गत रखा गया है। क्वाड्रिसाइकिल की लंबाई 3.6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती, इसमें 800cc से छोटा इंजन होना चाहिए, और इसका वजन 475 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

जीके फैक्ट

✧ बजाज ऑटो लिमिटेड क्वाड्रिसाइकल सेगमेंट के तहत व्यावसायिक रूप से 'क्यूट' (Qute) लॉन्च करने वाली पहली कंपनी थी। बजाज क्यूट को अप्रैल 2019 में CNG और पेट्रोल दोनों रूपों में भारत में लॉन्च किया गया था।

जैव विविधता संरक्षण पर पांच पहल

22 मई, 2020 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जैव विविधता संरक्षण पर पांच पहलें शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम' लॉन्च किया गया, जिसके तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऐसे छात्रों को जोड़ा जाएगा, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने के इच्छुक हैं।

- संकटग्रस्त प्रजातियों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) अभियान लॉन्च किया गया।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा यूएनईपी के साथ शुरू किए गए 'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' अभियान लांच किया गया, जो वन्यजीवों के अवैध व्यापार रोकने,जागरूकता बढ़ाने और समाधान की वकालत करता है।
- 'जैव विविधता संरक्षण और जैव-विविधता अधिनियम, 2002' पर एक वेबिनार शृंखला शुरू की गई। विश्व वन्यजीव कोष मॉडल कॉप (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) लांच किया गया, इस पहल में युवा पीढ़ी को शामिल किया गया है, ताकि वे हमारे अपने अस्तित्व के लिए जैव-विविधता पोषण के महत्व के बारे में बातचीत कर सकें।
- मानव जाति के लिए प्रदान की गई मुफ्त पारिस्थितिक सेवाओं के माध्यम से प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए विश्व वन्यजीव कोष द्वारा समर्थित एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया।

तेजस एमके–1 एफओसी विमान

27 मई, 2020 को भारतीय वायु सेना ने वायुसेना स्टेशन, सुलूर में 'तेजस एमके-1 एफओसी विमान' (Tejas Mk-1 FOC) को हाल में पुनर्जीवित किए गए नंबर '18 स्क्वैड्रन' जो कि फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वैड्रन है। इसे हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।

- 'तेजस एमके-1 एफओसी' एकल इंजन, हल्के वजन, बेहद

चुस्त, सभी मौसम में बहु-भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। हवा से हवा में ईंधन भरने में इसकी क्षमता इसे वाकई एक बहुमुखी प्लेटफार्म बनाती है।

- इस स्क्वैड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने किया।

अन्य तथ्य: भारतीय वायु सेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इस स्क्वैड्रन का हिस्सा थे।

जीके फैक्ट

✧ '18 स्क्वैड्रन' का गठन 15 अप्रैल, 1965 को अंबाला में फोलेंड जीनेट एयरक्राफ्ट के साथ किया गया। इस स्क्वैड्रन को अप्रैल 2016 में नंबर प्लेटेड किया गया था। यह स्क्वैड्रन दक्षिणी वायु कमान के परिचालन नियंत्रण में आता है।

मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ प्रजाति की मछली

मई 2020 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में सेथुकारई तट से एक दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है।

महत्वपूर्ण तथ्य: समुद्री घास के मैदानों के भीतर छलावरण करने वाली 'बैंड-टेल स्कॉर्पियोनफिश' (band-tail scorpion-fish) समुद्री घास के पारिस्थितिकी तंत्र के एक सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई। यह पहली बार था जब यह विशेष प्रजाति भारतीय जल में जीवित पायी गई।

- इसका वैज्ञानिक नाम 'स्कोर्पेनोस्पसिस नेग्लेक्टा' (Scorpaenospsis neglecta) है, जो कि चुभने वाली जहरीली रीढ़ और रंग बदलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है।
- तंत्रिका ऊतक के लिए हानिकारक रीढ़ में उपस्थित विष के कारण इस मछली को 'स्कोर्पियनफिश' कहा जाता है।
- मछली शिकारियों से बचने के लिए अपने आसपास के वातावरण के साथ रंग बदलने और मिश्रण करने की क्षमता रखती है।
- पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है, जो कि एक मूंगा कंकाल (Coral Skeleton) की तरह दिखाई देती है।
- जब इसकी विषयुक्त रीढ़ किसी व्यक्ति पर चुभती है, तो विष तुरंत व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जो बेहद दर्दनाक हो सकता है।



जीके फैक्ट

✧ मन्नार की खाड़ी तीन अलग-अलग तटीय पारिस्थितिक तंत्रों प्रवाल भित्ति, समुद्री घास और मैंग्रोव से संपन्न है। इसे समुद्री जैव विविधता (4223 पादप और जानवर प्रजाति) के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे विशाल क्षेत्र में से एक माना जाता है।

कोविड–19 भारत राष्ट्रीय सुपरमॉडल

मई 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने कोविड-19 संक्रमण के भविष्य में होने वाले प्रसार की निगरानी करने और इस प्रकार, स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी तथा संक्रमण में कमी लाने वाले अन्य उपायों से संबंधित निर्णय में सहायता करने के लिए एक 'कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपरमॉडल' की शुरुआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डीएसटी-एसईआरबी (विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड) तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित अन्वेषकों द्वारा कोविड-19 पूर्वानुमान एवं निरीक्षण के लिए अनगिनत गणितीय मॉडलों पर कार्य किया जा रहा है।

- मौसम संबंधी आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए गणितीय मॉडलों के उपयोग के भारत के इतिहास से प्रेरित होकर, डीएसटी ने एक मॉडल की प्रक्रिया आरंभ की है।
- पूरे देश के लिए एक मॉडल के लिए 'साक्ष्य-आधारित पूर्वानुमान' (मौसम पूर्वानुमान समुदायों में नियमित रूप से प्रचलित) के लिए आवश्यक कठोर परीक्षण किये जायेंगे।
- यह सफल साक्ष्य आधारित गणितीय और सांख्यिकीय पूर्वानुमान मॉडल को एकत्र करेगा और संक्रामक रोग के विस्तार के मजबूत पूर्वानुमान के लिए सर्वश्रेष्ठ भविष्यसूचक विश्लेषण को शामिल करेगा।
- इस सुपरमॉडल का उपयोग भारत एवं पूरे विश्व में संक्रमण के प्रसार की दर और स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में आने वाली कठिनाइयों से उबरने हेतु नीति निर्माताओं द्वारा किया जाएगा।

रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई, 2020 को युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ' (Responsible AI for Youth) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना और उन्हें नए युग के तकनीकी मांइड-सेट, प्रासंगिक एआई (कृत्रिम बुद्धिमता) कौशल-सेट और आवश्यक एआई टूल-सेट तक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ सशक्त बनाना, जिससे उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा इंटेल इंडिया की साझेदारी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से शुरू किया गया है।

- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राज्य शिक्षा विभागों को पात्रता मानदंडों के अनुसार शिक्षकों को मनोनीत करने में मदद करेगा।
- यह राष्ट्रीय कार्यक्रम देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूलों (केवीएस, एनवीएस, जेएनवी सहित) के कक्षा 8-12 के छात्रों के लिए है।
- पहले चरण में, प्रत्येक राज्य शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 10 शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 25-50 संभावित छात्रों की पहचान की जाएगी। छात्र एआई पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र द्वारा यह समझेंगे कि कैसे एआई के उपयोग से सामाजिक प्रभाव वाली विचारों/परियोजनाओं की पहचान की जाए।

मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ'

28 मई, 2020 को पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ' (Agneeprastha) की आधारशिला रखी गई।

उद्देश्य: 1981 से लेकर अब तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) की प्रतिकृति (Replica) के साथ की गई है, जो यूनिट द्वारा संचालित किए गए मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं।

- इन प्रदर्शनियों को स्क्रैप/अप्रयुक्त इन्वेंट्री से बनाया गया है, जिन्हें आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा रहा है।
- इसका मुख्य आकर्षण पी-70 'अमेटिस्ट' है, जो कि पुराने 'चक्र' (चार्ली-1 पनडुब्बी) के शस्त्रागार से पानी में प्रक्षेपित किया गया एक एंटी-शिप मिसाइल है, जो 1988-91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था।
- मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ' का निर्माण एक बार पूरा हो जाने के बाद, इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा, जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से पूर्वी नौसेना कमान के इस प्रमुख संचालन केंद्र में अपनी सेवाएं प्रदान की है।

जीके फैक्ट

✧ इस पार्क को वर्ष 2018-19 के लिए आईएनएस कलिंग के प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी दिया गया है।

बृहस्पति के पास खोजा गया क्षुद्रग्रह

मई 2020 में हवाई विश्वविद्यालय की 'एटलस प्रणाली' (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System -ATLAS) द्वारा एक दुर्लभ अन्तरिक्ष पिंड की खोज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस क्षुद्रग्रह को '2019 एलडी2' (2019 LD2) नाम दिया गया है। 2019 एलडी2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है। 2019 एलडी 2 एक विशेष प्रकार का क्षुद्रग्रह है, जिसे 'बृहस्पति ट्रोजन' कहा जाता है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है।

- इन्हें सक्रिय क्षुद्रग्रहों के रूप में जाना जाता है। शुरू में ये क्षुद्रग्रह प्रतीत होते हैं लेकिन बाद में इनमें धूमकेतु जैसे पूंछ विकसित हो जाते हैं।
- ट्रोजन क्षुद्रग्रह एक ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं, लेकिन कक्षा के साथ लगभग 60 डिग्री आगे या 60 डिग्री पीछे रहते हैं। पृथ्वी में कम से कम एक ट्रोजन क्षुद्रग्रह है और बृहस्पति के पास सैकड़ों हजारों हैं।
- बृहस्पति ट्रोजन की यह खोज इसलिए रोचक है कि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अधिकांश भाग कक्षा (Orbit) में लगभग चार अरब वर्ष पहले ही बह गया था। ऐसे में कोई भी सतही बर्फ जो गैस के रूप में बहुत पहले वाष्पीकृत हो गई होगी, उसे धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
- इस खोज से स्पष्ट होता है कि ट्रोजन (बृहस्पति) क्षुद्रग्रह की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ है। अब तक, उनकी सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के बारे में कोई सबूत नहीं था।

जीके फैक्ट

✧ 'एटलस' एक नासा द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसमें व्यापक क्षेत्र दूरबीनों (wide-field telescopes) द्वारा तेजी से आसमान को स्कैन करके पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने वाले क्षुद्रग्रहों का पता लगाया जाता है।

अमेरी आइस शेल्फ के विस्तार की संभावना

मई 2020 में गोवा स्थित 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (NCPOR) ने अंटार्कटिका में 'अमेरी आइस शेल्फ' (AIS) की सीमाओं के विस्तार में 2016 की स्थिति से 2021 तक 24 प्रशित और 2026 तक अतिरिक्त 24 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह भविष्यवाणी 16 साल के उपग्रह-आधारित प्रेक्षण पर आधारित है, जिसमें अमेरी आइस शेल्फ के 60,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर किया गया है।

- बर्फ की तैरती हुई चादरें जिन्हें 'आइस शेल्ज' (Ice shelves) कहा जाता है, हिमनद की स्थिरता को बनाए रखने में एक बहुआयामी भूमिका निभाती हैं। आइस शेल्फ एक हिमनद को भू-भाग से जोड़ते हैं।
- हिमनद के संतुलन के लिए हिम चादर का द्रव्यमान संतुलन (ice sheet mass balance), समुद्री स्तरीकरण (sea stratification) और तली जल विन्यास (bottom water formation) महत्वपूर्ण मापदंड हैं।
- समुद्र की सतह के तापमान में गिरावट का भी एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 15 वर्षों के दौरान आइस शेल्फ में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- अमेरी आइस शेल्फ दुनिया के सबसे बड़े हिमनद जल निकासी घाटियों में से एक है, जो अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों को कार्यान्वित करता है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी।

इंसुलिन के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल

बेंगलुरु स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साईंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) के वैज्ञानिकों ने मई 2020 में मधुमेह रोगियों में इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए 'सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल' विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिकों ने जैव-अनुकूल योगात्मक (Bio-compatible additives) का उपयोग करके सिल्क फाइब्रोइन (एसएफ) फॉर्म्युलेशन विकसित कर यह हाइड्रोजेल तैयार किया, जो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन वितरण में आसानी कर सकता है।

- उपयोग किए जाने वाले चिपचिपे योगात्मक ने 'सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन' (रेशम के कीड़ों द्वारा स्रावित रेशेदार प्रोटीन) की गतिशीलता को सीमित कर इसे तेजी से जेल में परिवर्तित किया।
- हाइड्रोजेल का चूहों में सक्रिय इंसुलिन देने में सफल प्रयोग किया गया है। चूहों में त्वचा के नीचे हाइड्रोजेल युक्त इंसुलिन के इंजेक्शन ने त्वचा के नीचे सक्रिय डिपो का गठन किया, जिसमें से इंसुलिन धीरे-धीरे बाहर निकलता है और 4 दिनों की लम्बी अवधि के लिए शारीरिक ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को बहाल रखता है।
- ज्ञात हो कि भारत में मधुमेह से लगभग 70 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं, जो विश्व में दूसरे स्थान पर हैं।

जीके फैक्ट

✧ मधुमेह शरीर के भीतर बीटा कोशिकाओं के नुकसान या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के परिणामस्वरूप होता है, जो ग्लूकोज होमियोस्टोसिस में असंतुलन पैदा करता है और रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि का कारण बनता है।

हर्बल दवा युक्त स्मार्ट बैंडेज

मई 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान' (IASST) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट बैंडेज विकसित की है, जो घाव तक दवा की सही डोज पहुंचाकर उसे ठीक कर सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरुप उसके पीएच स्तर को देखते हुए दवा की डोज जारी करती है। बैंडेज को नैनोटेक्नोलॉजी आधारित सूती पैच से बनाया गया है, जिसमें कपास और जूट जैसी टिकाऊ और सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।

- दवा को रिलीज करने के लिए जूट के कार्बन डॉट्स के साथ एक नैनोकॉम्पोजिट हाइड्रोजेल सुसंबद्ध कपास पैच बनाया गया।
- जूट का उपयोग पहली बार फ्लोरोसेंट कार्बन डॉट्स को संश्लेषित करने के माध्यम के रूप में किया गया है, जबकि पानी का उपयोग फैलाव माध्यम (Dispersion medium) के रूप में किया गया है।
- बैंडेज में इस्तेमाल हर्बल दवा में मूल रूप से 'अजादिराचिता इंडिका' (Azadirachta indica) अर्थात नीम के सत का उपयोग किया गया है।

जीके फैक्ट

✧ शुरुआती वर्षों में असम साइंस सोसायटी द्वारा पोषित 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान' का शुभारंभ 3 नवंबर, 1979 को नोबेल विजेता डोरोथी सी. हॉजकिन द्वारा किया गया था। 2009 से यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

आईसीजीएस सचेत

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई, 2020 को नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत 'आईसीजीएस सचेत' और दो अवरोधक नौकाओं (Interceptor Boats) का जलावतरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आईसीजीएस सचेत पांच अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला पोत है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है।

- 105 मीटर लंबे पोत सचेत का वजन लगभग 2350 टन है और यह 9100 किलोवाट के दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है।
- इसे 6000 नॉटिकल मील की सहनशक्ति के साथ 26 समुद्री मील (नॉट) की अधिकतम गति से चलने लायक डिजाइन किया गया है।
- यह पोत तेजी से बोर्डिंग और तलाश एवं बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले एक हेलिकॉप्टर, उच्च गति वाली चार नौकाओं और एक हवा से भरी जाने वाली एक नौका को ले जाने में सक्षम है।
- इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के दो अवरोधक नौकाओं 'सी-450' और 'सी-451' का भी जलावतरण किया। इन्हें लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड, हजीरा द्वारा देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- 30 मीटर लंबी दो नौकाएं 45 नॉट से भी अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम हैं। इन्हें उच्च गति अवरोधन (high-speed interception), तट के निकट गश्ती एवं कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है।

सुपर अर्थ ग्रह

'द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल' में प्रकाशित' शोध के अनुसार मई 2020 में कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड के खगोलविदों ने 'सुपर अर्थ' ग्रह की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुपर अर्थ का आकार और परिक्रमा पृथ्वी से मिलता-जुलता है। शोध के अनुसार, नए ग्रह का मेजबान तारा हमारे सूर्य का द्रव्यमान का लगभग 10 प्रतिशत है, जो ग्रह पर लगभग 617 दिनों का एक 'वर्ष' बनाता है।

- नए ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी और नेपच्यून के द्रव्यमान के बीच कहीं होगा।
- यह बहिर्ग्रह अपने मेजबान तारे की इतनी दूरी पर परिक्रमा करता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शुक्र और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच कहीं हो।

गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग तकनीक: 'सुपर अर्थ' को 'गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग तकनीक' का उपयोग करके खोजा गया था। यह एक अंतरिक्ष घटना पर आधारित है, जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूर के स्रोत से प्रकाश का आवर्धन होता है और यह निकट वस्तुओं को प्रकट करने में मदद करता है।

- ग्रह और उसके मेजबान तारे के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण ने एक अधिक दूर की पृष्ठभूमि वाले तारे से प्रकाश को एक विशेष तरीके से अवर्धित किया है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर

मई 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) के प्रकोप से असम में 15,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई, जिससे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इसके फैलने का खतरा हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस उन हजारों मृत जानवरों से फैल रहा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में बह रहे थे।

- ASF के पहले प्रकोप की चीन में अगस्त 2018 में पुष्टि की गई थी। इसके बाद मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस और इंडोनेशिया में इसका प्रकोप हुआ।
- 'पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन' के अनुसार ASF एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो जीवित या मृत सूअरों, घरेलू या जंगली सूअरों और सूअर के मांस उत्पादों द्वारा फैल सकता है।
- ASF 'एसफेरविरिडे' (Asfarviridae) परिवार के एक बड़े डीएनए वायरस के कारण होता है। हालांकि ASF और 'क्लासिकल स्वाइन फीवर' (CSF) के लक्षण समान हो सकते हैं, ASF वायरस CSF वायरस से भिन्न है।
- यह अत्यंत संक्रामक रोग संक्रमित सूअरों के रक्त, ऊतक और लार द्वारा फैल सकता है। दूषित भोजन और जूते, कपड़े, वाहन, चाकू और उपकरण जैसे संक्रमणी पदार्थ (Fomites) से भी संचरण हो सकता है। यह मनुष्यों में नहीं फैलता है।
- बीमारी का मुकाबला करने के लिए फिलहाल कोई टीका या दवा नहीं है। और मृत्यु दर 100 प्रतिशत है।

जीके फैक्ट

✧ ASF अफ्रीका, एशिया और यूरोप और के जंगली और घरेलू सूअरों में मौजूद है।

'स्वस्थवायु' वेंटिलेटर

सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलुरु ने मई 2020 में कोविड-19 के कम-गंभीर और गैर-आईसीयू वाले मामलों के उपयोग के लिए 36 दिनों में 'स्वस्थवायु' (SwasthVayu) वेंटिलेटर विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वर्तमान भारतीय कोविड-19 परिदृश्य में वार्डों, अस्थायी अस्पतालों, औषधालयों और घर में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए आदर्श है। स्वास्थ्यवायु एक माइक्रोकंट्रोलर-आधारित सटीक क्लोज-लूप एडेप्टिव कंट्रोल प्रणाली (closed-loop adaptive control system) है, जिसमें 'बिल्ट-इन बायोकम्पैटिबल कपलर' (built-in bio compatible coupler) और एक उच्च दक्षता युक्त पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगा है। ये अनोखी विशेषताएं वायरस के फैलने की आशंका को कम करने में मदद करती हैं।

- इसमें ऑक्सीजन सांद्रता अथवा संवर्धन इकाई को बाहर से जोड़ने की सुविधा है। इस प्रणाली को सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए 'एनएबीएल' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) से मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- इस मशीन का प्रमुख लाभ यह है कि यह सस्ती है और इसे बिना किसी विशेष नर्सिंग सहायता के इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसे अधिकांश स्वदेशी पुर्जों के साथ तैयार किया गया है।

अगप्पे चित्रा मैग्ना

21 मई, 2020 को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) ने चुंबकीय नैनोकण-आधारित आरएनए निष्कर्षण किट 'अगप्पे चित्रा मैग्ना' लॉन्च की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस किट को SCTIMST द्वारा विकसित किया गया है और इसे अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया था, इसलिए इसका नाम 'अगप्पे चित्रा मैग्ना किट' रखा गया है। अगप्पे चित्रा मैग्ना किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

- SARS - CoV - 2 का पता लगाने के लिए किट का उपयोग आरटी-लैंप (RT- LAMP), आरटी-पीसीआर (RT-PCR) और अन्य पीसीआर आधारित प्रोटोकॉल के आरएनए निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है।
- इस किट के जरिये रोगी के नमूने से आरएनए को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय नैनोकण वायरल आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर अत्यधिक शुद्ध और सान्द्र आरएनए देते है। यह किट अत्यधिक सस्ती है। ■■

BFSI बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये इस खंड की शुरुआत की गई है।

आरबीएल बैंक की कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग पहल

कोविड-19 के इस अभूतपूर्व समय के बीच सामाजिक दूरी और संपर्क रहित लेनदेन के लिए आरबीएल बैंक ने 21 मई, 2020 को कई संपर्क रहित (कॉन्टैक्टलेस) बैंकिंग पहलें शुरू की हैं। इसने निर्बाध, संपर्क रहित और सुविधाजनक बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए दिलचस्प डिजिटल पहलों जैसे रियलटाइम अपडेट के साथ व्हाट्सएप पर सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करना, जिसमें खाते की राशि, क्रेडिट कार्ड, उत्पादों और यहां तक कि नए डिजिटल खाते की जानकारी भी शामिल है। भारत में कहीं से भी तत्काल डिजिटल बैंक खाता शुरू किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से कागज रहित तथा वीडियो केवाईसी द्वारा संचालित है। बैंक मोबाइल ऐप में वर्चुअल डेबिट कार्ड सुविधा भी दे रहा है, जो बिना प्लास्टिक कार्ड की आवश्यकता के संपर्क रहित लेनदेन को सक्षम बनाता है। आरबीएल बैंक भारत के सबसे तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, पूर्व में इसे 'रत्नाकर बैंक' के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी।

आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन इयर एफडी

आईसीआईसीआई बैंक ने 21 मई, 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधि जमा (एफडी) योजना 'आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन इयर एफडी' लॉन्च की है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ तक जमा राशि के लिए 6.55% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करेगी। यह योजना 20 मई से 30 सितंबर, 2020 तक उपलब्ध है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन की बंद योजनाओं हेतु कोटक बैंक की मदद

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने बंद की छः योजनाओं के पोर्टफोलियो की परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और प्रभावित निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की ऋण पूंजी बाजार टीम को नियुक्त किया है। बाजार नियामक सेबी ने फंड हाउस को योजनाएं बंद करने के मामले में यूनिटधारकों के मतदान से पहले स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। ट्रस्टियों की सिफारिश पर स्वतंत्र सलाहकार योजनाएं बंद करने की पूरी प्रक्रिया में सहायता देंगे।

विश्व बैंक भारत को देगा 1 बिलियन डॉलर का पैकेज

कोरोना संकट के बीच 15 मई, 2020 को विश्व बैंक ने गंभीर रूप से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद हेतु सरकार के कार्यक्रमों के लिए 1 बिलियन डॉलर पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही विश्व बैंक की तरफ से भारत में आपातकालीन कोविड-19 सहायता के लिए दी गई राशि 2 बिलियन डॉलर हो गई है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मदद देने के लिए पिछले महीने 1 बिलियन डॉलर सहायता की घोषणा की गई थी।

फेडरल बैंक और मनीग्राम भुगतान प्रणाली साझेदारी

मई 2020 में भारत में अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, ताकि भारत में ग्राहकों के लिए बैंक खाता क्रेडिट विकल्प के लिए एक प्रत्यक्ष-प्रभावी पेशकश की जा सके। इस साझेदारी से लाखों लोगों को कोविड-19 संकट के दौरान अपने घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता के बिना और सुरक्षित रूप से सीधे अपने बैंक खातों में जमा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का चैटबोट 'पाई'

मई 2020 में रियल-टाइम आधार पर FASTag, RuPay, UPI तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एक कृत्रिम बुद्धिमता-आधारित चैटबोट 'पाई' (PAi) लॉन्च किया है। पाई NPCI, RuPay और UPI Chalega की वेबसाइटों पर पाठ्य भाग (टेक्स्ट) या आवाज (वॉइस) के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में NPCI उत्पादों की सही जानकारी देने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा। पाई को बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान से सम्बंधित कार्य करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है।

फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज समझौता

लॉकडाउन के दौरान डिजिटल और ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार के मद्देनजर फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा योजना के लिए बजाज

आलियांज से समझौता किया है। चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए उपभोक्ता मोटर बीमा पॉलिसियों को अपने फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए आनलाइन ही खरीद सकते हैं। मोटर-बीमा पॉलिसी निजी स्वामित्व वाले चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों को कवर करेगी। इससे मिलने वाले सुविधाओं में शामिल हैं- आसान ऑनलाइन खरीद और त्वरित दावा, 24×7 रोड-असिस्टेंस (Road assistance), मोटर ऑन-द-स्पॉट दावा निपटान के लिए स्व-परीक्षण।

सैमसंग पे डेबिट कार्ड

मई 2020 में दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय समूह सैमसंग अपने स्वयं के 'सैमसंग पे डेबिट कार्ड' लॉन्च करने की योजना बनाई है। SoFi के साथ साझेदारी में सैमसंग एक नया सैमसंग पे अनुभव पेश करेगा जिसमें एक नकद प्रबंधन खाते द्वारा समर्थित एक अभिनव डेबिट कार्ड होगा। सैमसंग पहले से ही अपने उपभोक्ताओं को 'सैमसंग पे' सेवा प्रदान कर रहा है। इस सेवा को अब पांच साल पूरे हो गए हैं। 'सैमसंग पे डेबिट कार्ड' सेवा सैमसंग पे ग्राहकों को अपने रोजमर्रा के वित्त पर निगरानी रखने में मदद करेगी।

केनरा बैंक गोल्ड लोन सुविधा

कोरोना वायरस के चलते लोगों के बीच नकदी के संकट को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कम ब्याज दर में सरल और सहज प्रक्रिया के साथ 18 मई, 2020 को स्वर्ण ऋण (गोल्ड लोन) सुविधा शुरू की है। बैंक ने 30 जून, 2020 तक विशेष गोल्ड लोन मुहिम शुरू की है। इस गोल्ड लोन पर ब्याज दर 7.85% प्रति वर्ष रखी गई है। बैंक के अनुसार इस ऋण का उपयोग ग्राहक कृषि से संबंधित काम, अपने पेशे से संबंधित काम, स्वास्थ्य से जुड़े खर्च और व्यक्तिगत जरूरतों आदि को पूरा करने में कर सकते हैं। बैंक की यह कर्ज सुविधा देश की चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध है। केनरा बैंक के चेयरमैन टी.एन. मनोहरन हैं।

सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2020 को मुंबई स्थित 'सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड' (CKP Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल और अस्थिर है। कोई ठोस पुनरुद्धार योजना या किसी अन्य बैंक के साथ विलयन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है तथा प्रबंधन की ओर से पुनरुद्धार के लिए विश्वसनीय प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती है। बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, अत: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 (3) (ए) का अनुपालन नहीं हो रहा है।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया कार्यशील पूंजी उत्पाद

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (SSFB) ने अपने 'सूक्ष्म वित्त संस्थान' (MFI) ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। एक लघु/सूक्ष्म ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ लॉन्च किए गए कार्यशील पूंजी उत्पाद बैंक के एमएफआई ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान उनकी चल निधि आवश्यकता (liquidity requirement) को पूरा करने में मदद करेंगे। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक बार में या किश्तों में 5000 रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में कार्यशील पूंजी उत्पाद त्रिची (तमिलनाडु) और कटक (ओडिशा) में दो शाखाओं में उपलब्ध हैं और जल्द ही इसे पूरे भारत में 100 शाखाओं तक विस्तारित किया जाएगा। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2017 में हुई थी। बस्कर बाबू रामचंद्रन बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ हैं।

कृष्णन रामचंद्रन मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक

मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने 5 मई, 2020 को कृष्णन रामचंद्रन को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। कृष्णन ने आशीष मेहरोत्रा का स्थान लिया। कृष्णन को स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान इंडस्ट्री में 23 साल का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में सेवाएँ दी थी।

प्रवीण कुमार भण्डारी ई-पैसा के सीईओ नियुक्त

क्लाउड-आधारित पॉइंट ऑफ सेल (PoS) ऐप ई-पैसा (ePaisa) ने मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) प्रवीण कुमार भंडारी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पदोन्नति से पहले, प्रवीण जून 2019 से ई-पैसा में मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) थे। CBO के रूप में, उनकी भूमिका संगठनों के भीतर और बाहर विकास के अवसरों को लागू करके व्यावसायिक विकास से संबंधित कार्यों और प्रक्रियाओं को शामिल करना था।

लक्ष्मीनारायण सुन्दरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक नियुक्त



अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने अप्रैल 2020 में डी लक्ष्मीनारायण को अपनी सहायक कंपनी सुंदरम होम फाइनेंस का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। लक्ष्मीनारायण ने श्रीनिवास आचार्य का स्थान लिया, जो 2010 से प्रबंध निदेशक थे। लक्ष्मीनारायण सुंदरम फाइनेंस ग्रुप के साथ एक दशक से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2019 में सुंदरम होम फाइनेंस ने 1,006.27 करोड़ रुपये की कुल आय और 145.48 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। सुंदरम फाइनेंस समूह की देश भर में 115 शाखाएँ हैं। ■■

B बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम PSUs

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

राजीव कुमार सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त

पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 29 अप्रैल, 2020 को तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी कुमार जुलाई 2019 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे और फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1987 के संकल्प द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय निकाय है, जिसे बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों में सलाह देना है।

'अमेजन पे लेटर' सुविधा

ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने 29 अप्रैल, 2020 को भारतीय ग्राहकों के लिए 'अमेजन पे लेटर' (Amazon Pay Later) सुविधा की घोषणा की। यह अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को तत्काल क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिसका उपयोग उत्पादों को खरीदने के साथ-साथ बिलों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। ग्राहक इस सुविधा से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक माह बाद या मासिक किश्त (ईएमआई) में मामूली ब्याज दरों पर 12 महीने तक भुगतान कर सकते हैं।

एनटीपीसी और ओएनजीसी का नवीकरणीय ऊर्जा हेतु संयुक्त उद्यम

भारत की शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी और देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने 21 मई, 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रारंभिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों भारत में और विदेश में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय बिजली परिसंपत्तियों की स्थापना करने तथा स्थिरता, भंडारण, ई-मोबिलिटी और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस) के अनुपालन वाली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशेंगी।

एयरटेल ने किया नोकिया से समझौता

भारती एयरटेल और नोकिया ने 28 अप्रैल, 2020 को भारत में नौ सर्किलों में नोकिया के SRAN सोल्यूशन को तैनात करने के लिए एक बहु-वर्षीय 1 बिलियन डॉलर के समझौते की घोषणा की। यह सोल्यूशन एयरटेल को अपने नेटवर्क की क्षमता विशेष रूप से 4जी को बढ़ाने में मदद करेगा और ग्राहक अनुभव में सुधार करेगा। जब देश भर में 5जी नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा तो नोकिया SRAN नेटवर्क एयरटेल को सर्वश्रेष्ठ संभव प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ गोपाल वित्तल हैं।

मारुति का 'बाय नाउ पे लेटर ऑफर'

मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL) ने 22 मई, 2020 को चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (CIFCL) के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य खरीदारों को अनुकूलित ऑटो खुदरा वित्तपोषण समाधान प्रदान करना है। इस वित्तपोषण समाधान को 'बाय नाउ पे लेटर ऑफर' (Buy Now Pay Later offer) नाम दिया गया है। इस ऑफर में 90% तक ऑन-रोड फंडिंग (On-road Funding) और दीर्घ अवधि के पुनर्भुगतान वाले ऋण शामिल हैं। CIFCL अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है।

जैक मा ने दिया सॉफ्टबैंक ग्रुप बोर्ड से इस्तीफा

चीन के अरबपति जैक मा ने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन बोर्ड से 18 मई, 2020 को इस्तीफा दे दिया है। चीन की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के सह-संस्थापक जैक 2007 में सॉफ्टबैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे तथा सॉफ्टबैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन के साथ उनके करीबी संबंध हैं। सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा में काफी निवेश किया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पहली बार किया कोयले का उत्पादन

अप्रैल 2020 में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उद्यम एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है। ओडिशा राज्य में तालाबिरा II और III खानों से कोयले का उत्पादन शुरूकिया गया है, इसकी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसे 2016 में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया था। इसका उपयोग मौजूदा और भविष्य में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। राकेश कुमार एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ■■

राज्य समाचार

हिमाचल प्रदेश

'निगाह' कार्यक्रम

मई 2020 में राज्य सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम 'निगाह' शुरू करने की योजना बनाई है।

- इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 'होम क्वारंटाइन' के दौरान सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए तैनात किया जाएगा।

पंजाब

पंजाब सदाचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020

कोविड-19 संकट के कारण राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कम रखने के लक्ष्य के अंतर्गत राज्य सरकार ने 17 मई, 2020 को 'पंजाब सदाचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020' जारी किया।

- नए प्रावधानों के अनुसार, कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है।
- इसके अलावा त्रैमासिक आधार पर अस्थायी रिहाई का लाभ उठाने की शर्त से भी छूट गई है।

हरियाणा

दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का पानी

राज्य ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

- राज्य ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत 2019-20 के दौरान 105,000 नल कनेक्शन प्रदान किए हैं।
- जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकार दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय लक्ष्य (2024-25) से आगे बढ़कर 100 प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज की योजना बना रही है।
- हरियाणा में 28.94 लाख परिवार हैं, जिनमें से 18.83 लाख परिवारों को पहले से नलों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 10.11 लाख घरों में से 2020-21 तक 7 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है।

जीके फैक्ट

- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'जल जीवन मिशन' की शुरूआत की गई है।

जम्मू – कश्मीर

'सुकून - कोविड-19 बीट द स्ट्रेस' पहल

लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग, जम्मू-कश्मीर ने मई 2020 में 'सुकून -कोविड-19 बीट द स्ट्रेस' (SUKOON' - COVID-19 Beat the Stress) नामक एक पहल शुरू की है।

उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहें और एक स्वस्थ मन के साथ कोविड -19 से संबंधित भय का सामना करें।

- यह कार्यक्रम दूरदर्शन कशिर चौनल पर हर मंगलवार को रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा, इस दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक 'मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य' जैसे मन को चिंता मुक्त रखने और तनाव पर नियंत्रण संबंधित अपने ज्ञान को साझा करेंगे।

बृजराज शर्मा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

मई 2020 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव बृजराज शर्मा को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे आयोग के 21वें अध्यक्ष होंगे।

- उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 93 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है।
- उनका कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने के साथ शुरू होगा तथा वे 62 वर्ष की आयु तक आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।

दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का पानी

जम्मू-कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

- वर्तमान वर्ष के दौरान, केंद्र-शासित प्रदेश 3 जिलों गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5,000 गांवों के 100% कवरेज के लिए योजना बना रहा है।
- जम्मू-कश्मीर में 18.17 लाख घर हैं, जिनमें से 5.75 लाख घरों को पहले ही चालू घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड

20 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंडश की शुरुआत की है। इसके लिए राज्य सरकार और सिडबी के बीच समझौता हुआ है।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक समारोह में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त सौंपी।
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक नई स्टार्ट-अप नीति की आवश्यकता है, ताकि राज्य में रोजगार सृजन की संभावनाओं को और मजबूत किया जा सके।
- स्टार्टअप्स पर यह पहल बड़ी संख्या में राज्य में आए प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करने में मदद करेगी।

'प्रवासी राहत मित्र' ऐप

राज्य सरकार ने 8 मई, 2020 को राज्य के उन प्रवासी कामगारों के लिए 'प्रवासी राहत मित्र' ऐप लॉन्च किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे हैं।

उद्देश्य: प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। बहुउद्देशीय ऐप प्रवासी कामगारों के कौशल से संबंधित नौकरियों और आजीविका प्रदान करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद करेगा। इन प्रवासी कामगारों का डेटा संग्रह ऐप के माध्यम से किया जाएगा।

- ऐप राज्य के राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है।

'आयुष कवच-कोविड' ऐप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई, 2020 को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद करने के लिए 'आयुष कवच-कोविड' ऐप लॉन्च किया।

- राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा विकसित यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित उपाय प्रदान करेगा।
- ऐप उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि कैसे तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसे रसोई में उपलब्ध सामग्री का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किया जा सकता है। ऐप उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ सलाह भी प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

21 मई, 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' का वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए शुभारंभ किया गया।

उद्देश्य: राज्य में फसल उगाने वाले किसानों को न्यूनतम आय की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में दी जाने वाली 5700 करोड़ रूपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित की।
- खरीफ 2019 से धान तथा मक्का की फसल के लिए किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से सहायता राशि दी जाएगी।
- गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर उचित और पारिश्रमिक मूल्य 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि (Exchange grant) 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है।
- इस योजना से लगभग 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

मध्य प्रदेश

'चरण पादुका' अभियान

अपनी तरह की पहली पहल में मध्य प्रदेश ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए 'चरण पादुका' अभियान शुरू किया है।

- इस अभियान के तहत, नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं।
- यह अभियान अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया।

'एफआईआर आपके द्वार' योजना

11 मई, 2020 को राज्य सरकार ने 'एफआईआर आपके द्वार' योजना शुरू की है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

- इस योजना के तहत, किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। एक जीपीएस

लगे हुए फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (FRV) में प्रशिक्षित हेड कांस्टेबल आपातकालीन कॉल (डायल 100) के माध्यम से कम गंभीर अपराध के लिए मौके पर एफआईआर दर्ज करेगा। गंभीर शिकायतों के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

- इस योजना के साथ राज्य के गृह मंत्री ने एक हेल्पलाइन 'डायल 112' भी शुरू की। यह तत्काल एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सेवा तथा अग्निशमन सेवा प्रदान करेगी।
- पुलिस विषय पर इस तरह की अभिनव योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ज्ञात हो कि पुलिस राज्य का विषय है।

जीके फैक्ट

✧ एफआईआर और इसकी वैधता को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 द्वारा परिभाषित किया गया है।

गुजरात

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14 मई, 2020 को लॉकडाउन से प्रभावित छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों के लिए 'आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना' की घोषणा की।

उद्देश्य: छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की मदद करना है।



- योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग एक लाख रुपये का गारंटी-मुक्त ऋण बैंकों से 2% वार्षिक ब्याज दर पर ले सकते हैं।
- योजना नियमों के तहत ऋण की अवधि तीन वर्ष की होगी और किस्त का भुगतान ऋण प्राप्त होने के छह महीने बाद ही शुरू होगा।
- ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

'सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान' का तीसरा चरण

राज्य में भूमिगत जलस्तर को ऊंचा उठाने के महत्वाकांक्षी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण 20 अप्रैल, 2020 को शुरू किया गया। यह अभियान 10 जून, 2020 तक चलाया जाएगा।

- योजना के तहत मानसून से पहले झीलों, रोधी-बांधों और नदियों का गाद निकालकर गहरा किया जाएगा और यह जन-भागीदारी के साथ-साथ मनरेगा के तहत किया जाएगा।
- कमजोर मानसून के बाद 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था, और आज तक राज्य की जल भंडारण क्षमता में 23,500 लाख क्यूबिक फीट की वृद्धि हुई है।

कर्नाटक

प्राणवायु कार्यक्रम

मई 2020 में बेंगलुरु नगर निगम ने लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की स्वयं जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए श्प्राणवायु कार्यक्रमश शुरू किया है।

- कोविड -19 के कारण कई मौतें गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (SARI) के कारण होती हैं। इसलिए प्राणवायु जागरूकता कार्यक्रम रक्त में निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों की मदद करने का प्रयास है, ताकि उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले वे अपनी जल्दी से जांच करा सकें।

केरल

मिशन 'ग्रैंड केयर'

मई 2020 में कोविड-19 निवारक उपाय के तहत पूरे राज्य में बुजुर्ग सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए नया मिशन 'ग्रैंड केयर' (Grand Care) शुरू किया जा रहा है। कुदुम्बश्री मिशन ने बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम 'ग्रैंड केयर' शुरू किया था, जो राज्य में बुजुर्गों और विदेश और अन्य स्थानों से आने वाले लोगों की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता दे रहा है।

- महिला स्व-सहायता समूह 'कुदुम्बश्री' शुरू से ही राज्य में कोविड-19 जागरूकता गतिविधियों का स्तम्भ है। महामारी की बुजुर्गों के लिए अतिसंवेदनशीलता के संदेश को प्रसारित करने के लिए समूह के विस्तृत नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।

ओडिशा

हेल्पलाइन 'भरोसा'

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के उन छात्रों के परामर्श के लिए 11 मई, 2020 को एक हेल्पलाइन 'भरोसा' का शुभारंभ किया, जो कोरोना वायरस के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

उद्देश्य: ओडिशा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक सेवाएं प्रदान करना।

- हेल्पलाइन नंबर 08046801010 को नई दिल्ली में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया गया था।

असम

धन्वंतरि योजना

असम सरकार ने 24 अप्रैल, 2020 को एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है, जिसके तहत मरीजों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं घर पर उपलब्ध कराई जा रही है। 200 रुपये से कम कीमत की दवाइयां मरीजों को मुफ्त में दी जाएंगी। स्वास्थ्यकर्मी उन रोगियों के लिए दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, जो अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे में इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ■■

खेल

चर्चित खेल व्यक्तित्व

बलबीर सिंह सीनियर

तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई, 2020 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में निधन हो गया।



- बलबीर सिंह ने तीन बार 1948 में लंदन में, 1952 में बतौर उप-कप्तान हेलसिंकी में और 1956 में बतौर कप्तान मेलबर्न में भारत की ओलंपिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1947 से 1958 तक के अपने शानदार खेल करियर में बलबीर ने 61 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 246 गोल किए। उन्होंने 1975 विश्व कप विजेता टीम के लिए एक प्रबंधक के रूप में भी काम किया।
- हेलसिंकी ओलंपिक (1952) फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ पांच गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्हें 1957 में पद्म श्री तथा 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
- हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड की हैसियत से खेलने वाले बलबीर का नाम अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में भी शामिल था।

दीपा मलिक

भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने 11 मई, 2020 को सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की।



- उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने से पूर्व ले लिया था। उन्हें फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया था।
- दीपा ने रियो पैरालंपिक खेल, 2016 की गोला फेंक (शॉटपुट) की F53 स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
- वर्ष 2019 में दीपा को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में उन्हें पद्म श्री और वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

उमर अकमल

अप्रैल 2020 में पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल को इस साल देश की प्रमुख टी-20 लीग 'पाकिस्तान सुपर लीग 2020' से पहले मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव की जानकारी देने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल के सभी प्रारूपों से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

नाओमी ओसाका

22 मई, 2020 को जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।



- फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की। दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 22 वर्षीय ओसाका ने कमाई के मामले में अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी सेरेना विलियम्स (3 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमाई) को पीछे छोड़ दिया है।
- इन दोनों ने हालांकि एक वर्ष में सर्वाधिक कमाई करने का मारिया शारापोवा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शारापोवा ने 2015 में दो करोड़ 97 लाख डॉलर की कमाई की थी।

एश्ले कूपर

22 मई, 2020 को आठ बार के ग्रैंड स्लैम विजेता महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एश्ले कूपर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्ण युग का हिस्सा रहे थे।

- उन्होंने चार एकल और चार युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। 1991 में इन्हें 'इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था।

पी.वी. सिंधु

बैडमिंटन विश्व चैंपियन पी.वी. सिंधु को 22 अप्रैल, 2020 को 'आई एम बैडमिंटन' (I am badminton) अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) द्वारा शुरू किया गया है।

- यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेल की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है।

सेबेस्टियन वेटल

चार बार के फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने 12 मई, 2020 को घोषणा की कि वह 2020 सत्र के बाद फेरारी का साथ छोड़े देंगे। यह दोनों पक्ष का संयुक्त फैसला है। वेटल के स्थान पर किसी अन्य ड्राइवर का चयन अभी तक नहीं किया गया है। वेटल ने इससे पहले रेडबुल की तरफ से एफवन में शानदार प्रदर्शन किया था और वह 2015 में फेरारी से जुड़े थे।



शेहान मदुशंका

श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मदुशंका को अवैध ड्रग्स (हेरोइन रखने) के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद 26 मई, 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

- उन्होंने ढाका में जनवरी, 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली थी। उन्होंने श्रीलंका के लिए 1 एकदिवसीय और 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

लुइगी गिगी सिमोनी

22 मई, 2020 को इटली की घरेलू फुटबॉल क्लब टीम इंटर मिलान को 1997-98 सत्र का यूएफा कप खिताब दिलाने वाले पूर्व कोच लुइगी गिगी सिमोनी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया।

मनमीत सिंह वालिया

पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का 11 मई, 2020 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में निधन हो गया। वे 58 साल के थे।

- वह पिछले लगभग दो साल से 'एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस- एएलएस' (Amyotrophic lateral sclerosis) से पीड़ित थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की गतिविधि पर असर पड़ता है।
- मनमीत 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस. श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वह 1981 से लगातार चार साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए।

सना मीर

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने 25 अप्रैल, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

- मीर ने 226 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें 2009 से 2017 तक बतौर कप्तान 137 मैच शामिल हैं। उन्होंने 120 वनडे मैचों में 151 विकेट लिए तथा 1630 रन बनाए जबकि 106 टी-20 मैचों में 89 विकेट चटकाए तथा 802 रन बनाए।

क्रिकेट

लार के उपयोग पर रोक की सिफारिश

18 मई, 2020 को पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने खेल शुरू होने पर कोविड-19 के जोखिमों को कम करने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार (Saliva) के उपयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

- हालांकि, समिति ने पसीने के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही किसी भी कृत्रिम (बाहरी पॉलिशिंग) सामग्री की अनुमति भी नहीं दी है।
- ज्ञात हो कि विशेष रूप से गेंदबाजों द्वारा गेंद को स्विंग करने के लिए तथा चमक बढ़ाने के लिए लार का इस्तेमाल किया जाता है।



- समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों से निपटने के लिए स्थानीय अंपायरों को अल्पावधि में मैचों के लिए नियुक्त किया जाए।
- इसने DRS के माध्यम से प्रति पारी रिव्यू में वृद्धि की भी सिफारिश की है।
- लार को प्रतिबंधित करने की सिफारिश केवल एक अंतरिम उपाय है और महामारी को नियंत्रण में लाने के बाद चीजें वापस सामान्य हो जाएंगी।

ऑस्ट्रेलिया पुरुषों की टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर

1 मई, 2020 को अद्यतन की गई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट से बादशाहत छिन गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गई है।

- टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम है।
- भारतीय टीम अक्टूबर 2016 से पहले स्थान पर काबिज थी। लेकिन अब भारतीय टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम के 116 रेटिंग अंक, न्यूजीलैंड के 115 रेटिंग अंक तथा भारतीय टीम के 114 अंक हैं।
- भारत की रैंकिंग में कमी की वजह अद्यतन की गई रैंकिंग में से 2016-17 के रिकॉर्ड को हटा दिया जाना है। भारत ने 2016-17 में 12 टेस्ट जीते थे और 1 टेस्ट हारा था।
- एकदिवसीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान तथा न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है।
- टी-20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर तथा भारत तीसरे स्थान पर हैं।

टेनिस

फेड कप हार्ट अवार्ड 2020

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 11 मई, 2020 को 'फेड कप हार्ट अवार्ड' जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं, जिन्हें यह सम्मान मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है।



- **उद्देश्य:** उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना, जिन्होंने फेड कप के दौरान अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कोर्ट पर असाधारण साहस दिखाया हो और टीम के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया हो।
- सानिया को एशिया ओसियाना क्षेत्र के लिए अवॉर्ड दिया गया। उन्हें कुल 16985 में से 10 हजार से अधिक वोट मिले। फेड कप हार्ट अवार्ड के विजेता का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है।
- सानिया ने चार साल बाद फेड कप में वापसी की और इतिहास में पहली बार भारत ने प्लेऑफ में जगह बनाई। उन्होंने 2000 डॉलर की पुरस्कार राशि तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया है।

जीके फैक्ट

✧ फेड कप हार्ट अवार्ड एक अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) की पहल है जिसे पहली बार 2009 में फेड कप फाइनल में प्रदान किया गया था। फेड कप 1963 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था।

फुटबॉल

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में अब 17 फरवरी से 7 मार्च, 2021 तक किया जाएगा।

- ज्ञात हो कि कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 21 नवंबर, 2020 तक भारत में होना था।
- कोस्टारिका/पनामा में आयोजित होने वाला 'अंडर -20 महिला विश्व कप 2020' भी 20 जनवरी से 6 फरवरी, 2021 तक पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि 'फीफा फुटसल विश्व कप 2020' का आयोजन 12 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2021 तक लिथुआनिया में होगा।
- नई तिथियों की घोषणा फीफा द्वारा की गई है।

फीफा ने स्थानापन्न नियमों में बदलाव को दी अस्थाई मंजूरी

विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने 8 मई, 2020 को स्थानापन्न नियमों में बदलाव को अस्थाई मंजूरी दे दी है।

- कोविड-19 के बाद के माहौल और व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए इस साल टीमों को प्रत्येक मैच में तीन के बजाय पांच स्थानापन्न (Substitute) रखने की अनुमति होगी।
- जो प्रतियोगिताएं या तो शुरू हो गई हैं या फिर शुरू होने वाली हैं, और 31 दिसंबर, 2020 तक पूरा होने वाली हैं, उनके लिए आईएफएबी (International Football Association Board - IFAB) ने कानून-3 (Law-3) में एक अस्थाई संशोधन के फीफा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस साल टीमों को प्रत्येक मैच में तीन के बजाय पांच स्थानापन्न रखने की अनुमति होगी।
- संशोधित नियम के अनुसार मैच में व्यवधान को कम करने के लिए प्रत्येक टीम के पास खेल के दौरान स्थानापन्न लेने के लिए अधिकतम तीन अवसर होंगे; मध्यांतर में भी स्थानापन्न लिए जा सकते हैं।
- यदि दोनों टीमें एक ही समय में स्थानापन्न लेती हैं, तो यह प्रत्येक टीम के लिए तीन अवसरों में से एक के रूप में गिना जाएगा।

विविध

फिडे चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेशंस कप

10 मई, 2020 को चीन ने 'फिडे चेस डॉट काम ऑनलाइन नेशंस कप' (FIDE Chess-com Online Nations Cup) शतरंज प्रतियोगिता जीत ली।



- सुपर फाइनल में चीन और यूएसए का स्कोर 2-2 से बराबरी पर रहा। चीन की टीम बेहतर अंक के आधार पर विजेता रही।
- छः टीमों के टूर्नामेंट के लीग दौर में चीन 17 अंक लेकर सबसे आगे रहा था। हालांकि उसे एकमात्र हार 10वें राउंड में यूएसए से ही मिली थी।
- भारतीय टीम पांचवें स्थान पर रही, जिसमें दिग्गज विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती, पी. हरिकृष्णा और बी. अधिबान, कोनेरू हंपी और डी. हरिका शामिल थीं।
- अन्य तीन टीमें यूरोप, रूस, शेष विश्व (Rest of the World) थीं।

36वें राष्ट्रीय खेल अनिश्चित काल के लिए स्थगित

28 मई, 2020 को गोवा में अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

- राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति सितंबर के आखिरी में बैठक करेगी और राष्ट्रीय खेलों की तारीख तय करेगी। पिछले राष्ट्रीय खेल केरल में 2015 में हुए थे। ■■

सार-संक्षेप

चर्चित व्यक्तित्व

रोबर्टो एजेवेडो

14 मई, 2020 को विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले ही त्यागपत्र देने का फैसला किया है।



- ब्राजील के पूर्व राजनयिक एजेवेडो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव की वजह से अपना पद समय से पहले ही 31 अगस्त, 2020 को छोड़ देंगे। ज्ञात हो कि ट्रम्प ने विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था।

बेंजामिन नेतन्याहू

इजरायल में 17 मई, 2020 को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ले ली। वे पाँचवीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने।

- चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंद्वी से साथी बने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गांत्ज के साथ मिलकर सरकार बनाई है।
- ज्ञात हो कि इस्राइल में एक साल में तीन बार आम चुनाव हो चुके हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और गांत्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया।

रवींद्रनाथ टैगोर

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 7 मई, 2020 को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'गुरुदेव- जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रु हिज विजुअल वोकैबुलरी' (Gurudev – Journey of the Maestro through his visual vocabulary) शीर्षक के तहत एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया।



- 1861 में जन्मे रवींद्रनाथ टैगोर को 'गुरुदेव' के नाम से जाना जाता है। उन्हें मुख्य रूप से लेखक, कवि, नाटककार, दार्शनिक, संगीतकार एवं कोरियोग्राफर और चित्रकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थान 'विश्व-भारती' की स्थापना की थी।
- वह वर्ष 1913 में अपने उपन्यास श्गीतांजलिश के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत भी लिखे।

मनीषा सिंह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 5 मई, 2020 को वरिष्ठ भारतीय-अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।

- वे वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सहायक सचिव हैं। उनका पद राजदूत के समकक्ष होगा।

दीया मिर्जा

मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के कार्यकाल को वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था।



- भारतीय अभिनेत्री दीया मिर्जा और अलीबाबा के प्रमुख जैक मा उन 17 वैश्विक हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिये कार्रवाई और वैश्विक राजनैतिक इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिये नया पैरोकार नियुक्त किया है।

जामिनी रॉय

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने वर्चुअल टूर के माध्यम से पथ-प्रदर्शक कलाकार जामिनी रॉय को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 11 अप्रैल, 1887 को हुआ था।



- 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में पेंटिंग की ब्रितानी अकादमिक शैली में प्रशिक्षित, जामिनी रॉय एक कुशल चित्रकार थे। वे अबनिंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे।
- उन्होंने कालीघाट पेंटिंग में अपने शिल्प को बेहतर ढंग से चित्रित करने के लिए, मूर्तियों के पारंपरिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध समुदाय 'पटुआ' से प्रशिक्षण लिया था। उन्हें 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

राजा रवि वर्मा

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 29 अप्रैल, 2020 को प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी 172वीं जयंती पर एक वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी।



- राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा काफी हद तक यूरोपीय शैली के एक स्व-प्रशिक्षित चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा तैल चित्रण में कुशल थे और उन्होंने यूरोपीय प्रकृतिवाद की शैली के साथ एक बेजोड़ सामंजस्य स्थापित किया था।
- माना जाता है कि वर्मा ने 58 साल की उम्र में अपनी मृत्यु से पहले लगभग 7,000 पेंटिंग बनाई थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में 'दमयंती का हंस से बात करना', 'शकुंतला-दुष्यंत' तथा 'शांतनु और मत्स्यगंधा' शामिल हैं।
- 1904 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 2013 में उनके सम्मान में बुध ग्रह पर एक 'क्रेटर या गड्ढा' (Crator) को उनके नाम से नामित किया गया था।

चर्चित स्थल

तमिलनाडु

मई 2020 में तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु एक साल बढ़ाकर 59 कर दी गई है।

- यह आदेश महामारी के कारण राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है।

निधन

वाजिद खान

1 जून, 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे।



- वे अपने भाई साजिद खान के साथ बनाई जोड़ी साजिद-वाजिद के लिए लोकप्रिय थे।
- उन्होंने वर्ष 1998 में फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' से बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था।
- इसके बाद उन्होंने 'हैलो ब्रदर', 'चोरी चोरी', 'गर्व', 'मुझसे शादी करोगी', 'तेरे नाम', 'पार्टनर' तथा 'दबंग' जैसी फिल्मों में संगीत दिया था।

बेजान दारुवाला

प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारुवाला का 29 मई, 2020 को अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे।

- दारुवाला का नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित 'द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी' (The Millennium Book of Prophecy) में पिछले 1,000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था।
- उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जीत शामिल थी।

अजीत जोगी

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई, 2020 को रायपुर में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे।



- वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2003 तक इस पद पर रहे।
- उन्होंने जून 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर 'जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़' के नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था।
- इंजीनियरिंग स्नातक और आईएएस अधिकारी रहे जोगी 2 बार लोकसभा सदस्य तथा 1986 से 1998 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे।

योगेश गौड़

राजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'आनंद' में प्रसिद्ध गीतों 'कहीं दूर जब दिन ढल जाए' और 'जिंदगी कैसी है पहेली' के गीतकार योगेश गौड़ का 29 मई, 2020 को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे।



- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म 'सखी रॉबिन' से की थी। उन्होंने हृषिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया था। उन्होंने कई फिल्मों जैसे 'मिली', 'रजनीगंधा', 'बातों बातों में' और 'छोटी सी बात' के लिए कुछ बेहतरीन गाने लिखे।
- गीतकार के रूप में योगेश की आखिरी पेशकश 2017 की फिल्म 'अंग्रेजी में कहते हैं' थी।

एम.पी. वीरेंद्र कुमार

मलयालम लेखक, पत्रकार और राज्यसभा सदस्य एम.पी. वीरेंद्र कुमार का 28 मई, 2020 को कोझिकोड में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

- 2016 में हिमालय पर यात्रा वृत्तांत 'हैमवाता भूमिइल' के लिए उन्हें मूर्तिदेवी पुरस्कार दिया गया था। वह मलयालम दैनिक समाचार पत्र 'मातृभूमि' के प्रबंध निदेशक भी थे।
- वीरेंद्र कुमार 1987 में केरल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह दो बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। वह अप्रैल 2016 से राज्यसभा के सदस्य थे।

श्यामला जी. भावे

विख्यात शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी. भावे का 22 मई, 2020 को बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 79 वर्ष की थीं।

- भावे ने ज्यादातर हिंदुस्तानी शैली में संगीत प्रस्तुति दी थी, लेकिन वे कर्नाटक संगीत में भी पारंगत थी। इस कारण उन्हें 'उभयगान विदुषी' की उपाधि दी गई थी। उन्हें 'कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था।

रत्नाकर मतकरी

प्रसिद्ध मराठी नाटककार, साहित्यकार, रंगमंच के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक, रत्नाकर मतकरी का 17 मई, 2020 को मुंबई में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे।



- उन्हें उनकी संगीत रचनाओं के लिए संगीत नाटक अकादमी (वर्ष 2003) और साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। उनकी फिल्म 'इन्वेस्टमेंट' को क्षेत्रीय श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।
- उनका पहला नाटक 'वेदी मनसा', जो 17 साल की उम्र में लिखा गया था, पहली बार आकाशवाणी मुंबई पर प्रसारित किया गया था।
- उनके कुछ प्रसिद्ध मराठी नाटकों में महाभारत पर आधारित 'अरण्यक', 'लोक कथा 78', 'दुभंग', 'अश्वमेध', 'चार दिवस प्रेमचे' और 'इंदिरा' शामिल हैं। उनके बाल नाटक 'अलबत्या गलबत्या' और 'निम्मा शिम्मा राक्षस' बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय थे।

संत शोभन सरकार

प्रसिद्ध संत स्वामी विरक्त आनंद महाराज उर्फ शोभन सरकार का 13 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के शिवली क्षेत्र में निधन हो गया।



- छिपे हुए कई टन सोने के बारे में अपने सपने के बाद वह तब सुर्खियों में आए थे, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम वर्ष 2013 में सोने की खुदाई के लिए उत्तर प्रदेश आई थी।
- उनके सपने ने एएसआई को उन्नाव जिले के डुंडिया खेड़ा गांव में छिपे हुए सोने के खजाने की खुदाई करने और इसका पता लगाने के लिए प्रेरित किया था।

साई गुंडेवर

'पीके', 'बाजार' और 'रॉक ऑन' जैसी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता साई गुंडेवर का 10 मई, 2020 को लॉस एंजेलिस में निधन हो गया।

- वे 42 वर्ष के थे। वे ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे।

हरिशंकर वासुदेवन

10 मई, 2020 को प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोरोना संक्रमण से कोलकाता में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे।

- वह यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत-रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मध्य एशिया कार्यक्रम की स्थापना की थी। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) में सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्यपुस्तक विकास समिति के प्रमुख के रूप में और बाद में 2007 से मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था।

लिटिल रिचर्ड

मशहूर अमेरिकी गायक और संगीतकार लिटिल रिचर्ड का 9 मई, 2020 को 87 साल की उम्र में निधन हो गया।

- लिटिल रिचर्ड का जन्म जॉर्जिया (अमेरिका) में हुआ था। उनका पूरा नाम रिचर्ड पेन्निमन था।
- लिटिल रिचर्ड का एलमब 'रॉक एन रोल (rock 'n' roll)' बहुत मशहूर हुआ। उन्हें उनके गाने 'टुट्टी फ्रूटी' (Tutti Frutti) और 'लॉन्ग टॉल सैली' (Long Tall Sally) के लिए भी जाना जाता है।

दलित एजिलमलाई

अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे दलित एजिलमलाई (Dalit Ezhilmalai) का 6 मई, 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे।

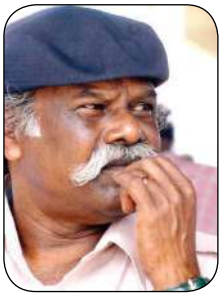

- 1989 में पट्टली मक्कल काची (पीएमके) के गठन के बाद वह पार्टी में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। 1998 के लोकसभा चुनाव में, वह चिदंबरम (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे।
- बाद में वे AIADMK पार्टी में शामिल हो गए थे।
- एजिलमलाई ने 1963 और 1987 के बीच पूर्ववर्ती डाक एवं टेलीग्राफ विभाग में सेवा दी थी। इस अवधि के दौरान, उन्हें 1974 तक पाँच वर्षों के लिए सेना में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था और उन्हें सेना में सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक से नवाजा गया था।

अजय कुमार त्रिपाठी

भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का 2 मई, 2020 को एम्स, नई दिल्ली में निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे।

- उन्होंने 27 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे।

सार–संक्षेप

के.एस. निसार अहमद

प्रख्यात कन्नड़ कवि के.एस. निसार अहमद का 3 मई, 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उन्हें 'नित्योत्सव कवि' के नाम से भी जाना जाता था।

- पेशे से भूगर्भशास्त्र के प्रोफेसर, अहमद एक विपुल कवि और लेखक थे। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं में कार्य किया जैसे- आलोचना, बाल साहित्य, कई शेक्सपियर के नाटकों का कन्नड़ में अनुवाद आदि।

रोनाल्ड विवियन स्मिथ

दिल्ली के प्रतिष्ठित इतिहासकार और इतिवृत्त लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का 30 अप्रैल, 2020 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।



- उन्होंने 1956 से ही अखबारों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में समाचार एजेंसी 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' और 'द स्टेट्समैन' अखबार के लिए काम किया। 1996 में वह 'द स्टेट्समैन' से बतौर समाचार संपादक पद से सेवानिवृत्त हुए।
- उनकी अधिकांश पुस्तकें दिल्ली पर आधारित हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं- 'देल्ही: अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी' (Delhi: Unknown Tales of a City), 'द देल्ही दैट नो वन नोज' (The Delhi That No-One Knows), 'लिंगरिंग चार्म ऑफ देल्ही: मिथ, लोर एंड हिस्ट्री' (Lingering Charm Of Delhi: Myth, Lore and History) तथा 'द ताज मिथ एंड रिएलिटी' (The Taj Myth and Reality) आदि।
- स्मिथ को इतिहास, पुरातनता, एजिप्टोलॉजी (मिस्र की भाषा, इतिहास और सभ्यता का अध्ययन), रहस्यवाद की जानकारी हासिल करना और उन पर लिखना पसंद था।
- उन्हें 'कैनन हॉलैंड प्राइज' और 'रोटरी अवार्ड फार जनरल नॉलेज' और 1997-98 में कोलकाता के माइकल मधूसूदन अकादमी की ओर से पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

डेनिस गोल्डबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का 29 अप्रैल, 2020 को केपटाउन में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे।



- गोल्डबर्ग वर्तमान में सत्तारूढ़ 'अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस' के एक प्रमुख सदस्य थे। नेल्सन मंडेला के सहयोगी रहे गोल्डबर्ग ने श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लाई गई उत्पीड़न की जातिवादी व्यवस्था तथा रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में 22 साल जेल में बिताए।

जरीना हाशमी

मशहूर भारतीय कलाकार जरीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल, 2020 को लंदन में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थीं।

- 1937 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मी, जरीना अपने समय की कुछ प्रसिद्ध महिला भारतीय कलाकारों में से एक थीं। उनका काम न्यूनतम ड्राइंग (Minimal drawing) से लेकर प्रिंटमेकिंग और मूर्तिकला तक था।

नियुक्ति

आभास झा

भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में दक्षिण एशिया में 'जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक' के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी जिम्मेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को वैश्विक व्यवहार सीमाओं में जोड़ने और संगठित करने की होगी।



- आभास बिहार की राजधानी पटना स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। अभास ने इससे पहले बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी सेवाएँ दी हैं।

मार्कोस ट्रायजो

27 मई, 2020 को ब्राजील के मार्कोस ट्रायजो को भारत के के.वी. कामथ की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के अनिल किशोरा बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी होंगे।

मनोज आहूजा

12 मई, 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर वह अनीता करवाल का स्थान लेंगे



- वह वर्ष 1990 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व में वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

तरुण बजाज

मई 2020 में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक

के रूप में नियुक्त किया है। इस पद पर वह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त हुए।

- तरुण बजाज ने 1 मई से आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया।
- आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे।

अरविंद कुमार शर्मा

अरविंद कुमार शर्मा ने 1 मई, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया।

- इस नियुक्ति से पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

टी.एस. तिरुमूर्ति

केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल, 2020 को टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है।

- वह देश के सबसे प्रमुख राजनयिकों में से एक सैयद अकबरुद्दीन से पदभार ग्रहण करेंगे, जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
- 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी तिरुमूर्ति ने मलेशिया में उच्चायुक्त व इंडोनेशिया में मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी सेवाएं दी हैं।

शिखा शर्मा

अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल की डिजिटल भुगतान शाखा 'गूगल पे इंडिया' की नई सलाहकार नियुक्त की गई हैं।



- उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए की गई है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। 'गूगल पे' यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो अमेजन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई सुविधा प्रदान करता है।

पुरस्कार/सम्मान

पुलित्जर पुरस्कार 2020

4 मई, 2020 को 15 पत्रकारिता श्रेणियों और सात 'पुस्तक, नाटक और संगीत' श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार 2020 विजेताओं की घोषणा की गई।

- इस बार भारत की ओर से 5 फोटो जर्नलिस्ट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारत के लिए 'एसोसिएटेड प्रेस' के तीन फोटोग्राफर (मुख्तार खान, डार यासिन और चन्नी आनंद) को 'फीचर फोटोग्राफी' (Feature Photography) श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



- उन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में बंद के दौरान 'जीवन पर अद्भुत चित्र' (Striking images on life) के लिए सम्मानित किया गया है। यासिन और मुख्तार श्रीनगर के निवासी है जबकि चन्नी आनंद जम्मू में रहते हैं।
- इसके अलावा अनुश्री फड़नवीस और अदनान आबिदी ने 'ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी' श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया, जिन्होंने वर्ष 2019 में हांगकांग में नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों की कवरेज की थी।

जीके फैक्ट

- समाचार पत्र के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाने वाला पत्रकारिता और कला का पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में दिया गया था। इसे यूएसए में क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।

मेजर सुमन गवानी को 'संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द इयर पुरस्कार'

वर्ष 2019 में 'दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन' (UNMISS) में महिला शांतिदूत के रूप में सेवाएं देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को 29 मई, 2020 को प्रतिष्ठित 'संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द इयर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।



- मेजर सुमन को यह अवार्ड ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डी कास्त्रो अरुजो (Carla Monteiro de Castro Araujo) के साथ संयुक्त रूप से दिया गया।
- 2018 में UNMISS में तैनाती के बाद मेजर सुमन ने संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के बारे में संयुक्त राष्ट्र सेना के 230 प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक अभियान में महिला सैन्य प्रेक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की है।

जीके फैक्ट

- 2016 में स्थापित 'संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द इयर पुरस्कार' एक शांति अभियान के संदर्भ में महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संकल्प 1325' के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक व्यक्तिगत सैन्य शांतिदूत के समर्पण और प्रयास को मान्यता प्रदान है।

सार–संक्षेप

'अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज' की सदस्यता के लिए तीन भारतीय चयनित

अप्रैल 2020 में 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज' (American Academy of Arts and Sciences) की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्यता के लिए तीन भारतीयों को चुना गया है।

- इनमें से दो विज्ञान में हैं- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के 'सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट' से बिमन बागची और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR), बेंगलुरु से शोभना नरसिम्हन।
- मानविकी और कला स्ट्रीम के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स' से कविता सिंह चुनी गई हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्यों की पूर्व की सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं।

जीके फैक्ट

✧ 1780 में स्थापित 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज' उन विद्वानों और नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित करती है, जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया हो तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत किया हो।

किम जोंग द्वितीय विश्वयुद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित

5 मई, 2020 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल प्रदान किया है।



- किम की ओर से उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन-ग्वोन ने रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मेत्सेगोरा के हाथों यह मेडल प्राप्त किया।
- किम को यह सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया, जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में मौत हुई थी।

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार 2020

मई 2020 में आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार की ओर से 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- यह पुरस्कार उन्हें दो आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनोइलेक्ट्रोनिक उपकरणों से परे ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है।
- वैन डेर वाल्स सामग्री अत्यंत-पतली परतों से बनती हैं, जो कमजोर वैन डेर वाल्स बॉन्ड द्वारा एक साथ रखी जाती हैं। ये तब दृष्टिगोचर होती हैं जब परमाणु निकटता में होते हैं। 'ग्राफीन' एक वैन डेर वाल्स सामग्री है।

अभियान/सम्मेलन/आयोजन

सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020

27 से 29 मई, 2020 तक 'सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020' नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- यह वर्ष में दो बार आयोजित होने वाला शीर्ष स्तर का सम्मेलन है, जिसमें वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा और आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

'वंदे भारत' मिशन

कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14800 भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन 'वंदे भारत' के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 7 से 13 मई, 2020 तक 64 उड़ानें संचालित की।



- इन 64 उड़ानों में दस उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से, दो कतर से, पांच सऊदी अरब से, सात ब्रिटेन से, पांच सिंगापुर से, सात अमेरिका से, पांच फिलीपींस से, सात बांग्लादेश से, दो बहरीन से, सात मलेशिया से, पांच कुवैत से और दो उड़ानें ओमान से संचालित की गई।

'नदी प्रबंधन का भविष्य' पर एक आइडियाथॉन

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) ने 1 मई, 2020 को 'नदी प्रबंधन का भविष्य' पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। आइडियाथॉन में मौजूदा चुनौतियों के नए संभावित समाधानों हेतु विचार मंथन किया जाता है।

- **उद्देश्य:** इस बात की जांच करना कि संकटों से निपटने के लिए नदियों की सामाजिक दृष्टिकोण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? महामारी (कोविड-19) ने हमें नदी प्रबंधन के लिए क्या-क्या सबक सिखाया है? और नदी संकट की स्थिति में किस प्रतिक्रिया वाले तंत्र की आवश्यकता है?

युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

ऑपरेशन 'समुद्र सेतु'

भारतीय नौसेना ने मई 2020 में कोविड-19 के कारण विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन 'समुद्र सेतु' शुरू किया है।

- भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज 'जलश्वा' (INS Jalashwa) और 'मगर' (INS Magar) ने मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह से समुद्र सेतु के चरण–1 के भाग के रूप में 8 मई, 2020 से निकासी अभियान शुरू किया ।

मिशन 'सागर'

10 मई, 2020 को भारत सरकार ने कोविड–19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम 'मिशन सागर' लॉन्च किया।



- मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज 'केसरी' को खाद्य वस्तुओं सहित कोविड–19 सम्बन्धित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई, 2020 को 5 देशों मालदीव,मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना किया गया।
- 'मिशन सागर' के रूप में यह तैनाती भारत के प्रधानमंत्री की 'हिंद महासागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास –सागर' (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) की संकल्पना के अनुरूप है और भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है।

आईएनएस कलिंगा में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

भारत सरकार के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा के लक्ष्य के अनुरूप 28 मई, 2020 को विशाखापत्तनम में आईएनएस कलिंगा में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन (कमांडिंग–इन–चीफ, ईस्टर्न नेवल कमांड) ने 2 मेगा वाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का उद्घाटन किया।

- ईस्टर्न नेवल कमांड में सबसे बड़े इस संयंत्र की अनुमानित सक्रियता अवधि 25 वर्ष है। आईएनएस कलिंगा ने 1980 की शुरुआत में अपनी गठन के बाद से हरियाली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- इनमें वन रोपण, कई पौधारोपण अभियान, तटीय क्षेत्रों का सफाई अभियान, भौगोलिक विरासत स्थल 'एरा मैटी डिब्बालू' (Erra Matti Dibbalu) की सुरक्षा जैसे कई काम शामिल है।

समझौते/संधि

भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक

स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए 8 मई, 2020 को भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का यह पहला समझौता है। इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा और आपातकर्मियों, सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों तथा राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतें पूरी होंगी।
- इससे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को बेहतर बनाना और संक्रामक रोग वाले अस्पतालों का जीर्णोद्धार भी संभव होगा।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार हेतु समझौता

भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (डीवीसीए) में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 15 मई, 2020 को 145 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना से पश्चिम बंगाल के 393,964 हेक्टेयर क्षेत्र के पांच जिलों में लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हर साल आने वाली बाढ़ से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
- परियोजना का कुल मूल्य 413.8 मिलियन डॉलर है, यह एआईआईबी (145 मिलियन डॉलर), आईबीआरडी (145 मिलियन डॉलर) और पश्चिम बंगाल सरकार (123.8 मिलियन डॉलर) के बीच सह–वित्तपोषित है।

सीएसआईआर, इंटेल इंडिया और आईआईआईटी हैदराबाद में साझेदारी

सार्स- सीओवी–2 (SARS-CoV-2) का संचरण (ट्रांसमिशन) कम करने के लिए जोखिम वाले रोगियों पर तेजी से परीक्षण और भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करने के लिए सीएसआईआर, इंटेल इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी), हैदराबाद के साथ साझेदारी में काम कर रहा है।

- **उद्देश्य:** सहरूग्णता वाले रोगियों (Patients with co-morbidities) के लिए महामारी विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमता–आधारित जोखिम स्तरीकरण को समझने के लिए तेजी से और कम खर्चीली कोविड–19 जांच और कोरोनावायरस जीनोम अनुक्रमण प्राप्त करना।
- पहल के एक हिस्से के रूप में इंटेल इंडिया एक एंड–टू–एंड सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसमें कई एप्लिकेशन, परीक्षण उपकरण, डेटा कलेक्शन / एग्रीगेशन गेटवे और एआईमॉडल–हब प्लेटफॉर्म (AI model-hub platform) शामिल हैं।
- सीएसआईआर की सहायक प्रयोगशालायें जैसे सीएसआईआर–आईजीआईबी, सीएसआईआर–सीसीएमबी आदि अन्य विभिन्न अस्पतालों और नैदानिक श्रृंखलाओं के साथ मिलकर विस्तृत निदान करेंगे।
- आईआईआईटी–हैदराबाद जोखिम स्तरीकरण एल्गोरिदम या प्रणाली (algorithms) विकसित करेगा, जो महामारी का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक तैयारी के रूप में औषधि और टीके की खोज में मदद कर सकता है।

सार–संक्षेप

कला/संस्कृति

संस्कृति पर्व पत्रिका विशेषांक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मई, 2020 को वीडिओ काफ्रेंसिंग के द्वारा संस्कृति पर्व पत्रिका के विशेषांक 'भारत 1946-2020, नोआखाली से दिल्ली तक' के ई-संस्करण का लोकार्पण किया।

- पत्रिका संस्कृति पर्व के इस विशेषांक में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय का अंतिम वक्तव्य, जो 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था, उसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

वेब पोर्टल/ऐप

राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल

सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 30 मई, 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किया गया।

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग और आईटी उद्योग का नैसकॉम संयुक्त रूप से मिलकर इस पोर्टल को संचालित करेगा।
- यह पोर्टल भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। भारत में एआई से संबंधित लेखों, स्टार्ट-अप, एआई में निवेश फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों जैसे संसाधनों को साझा करेगा। इसके द्वारा पोर्टल पर दस्तावेजों, केस स्टडी, अनुसंधान रिपोर्ट आदि को भी साझा किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली

मई 2020 में प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों का आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड 'राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली' विकसित किया है।

- यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय संग्राहक (Central repository) की तरह कार्य करेगा और उनके मूल स्थानों तक यात्रा को सुचारु बनाने के लिए अंतर-राज्यीय संचार/ समन्वयमें मदद करेगा।
- इसका एक अतिरिक्त लाभ कोविड-19 मरीजों के सम्पर्क में आने वालों का पता लगाने (कॉन्ट्रेक्ट ट्रसिंग) के रूप में भी होगा।

चैंपियन्स पोर्टल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून, 2020 को एमएसएमई सेक्टर के लिए 'चैंपियन्स' (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength - CHAMPIONS) पोर्टल लॉन्च किया।

- **उद्देश्यः** वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति, आदि के संदर्भ में इस कठिन स्थिति में एमएसएमई की मदद करना; एमएसएमई को चिकित्सा वस्तुओं और सामानों के विनिर्माण हतु अवसर प्रदान करने में मदद करना; उभरते हुए एमएसएमई की पहचान करना, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं।
- इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुडी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।
- यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी टूल्स के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है।

आयुष संजीवनी ऐप

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 7 मई, 2020 को 'आयुष संजीवनी ऐप' का शुभारम्भ किया।

- ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ ही कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायता मिलेगी।

गरुड़ पोर्टल

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 5 मई, 2020 को 'गरुड़ पोर्टल' लॉन्च किया।

- **उद्देश्यः** कोविड-19 से संबंधित आरपीएएस (रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम) / ड्रोन संचालनों के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक यानी तेजी से सशर्त छूट प्रदान करना।



- गरुड़ 'राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग का सरकारी प्राधिकरण' (Government Authorization for Relief Using Drones - GARUD) का संक्षिप्त रूप है।
- सशर्त छूट कोविड-19 से संबंधित हवाई निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए एक सरकारी संस्था द्वारा तैनात आरपीएएस/ड्रोन तक सीमित होगी।
- आरपीएएस के सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित सरकारी संस्था के पास होगी। प्रत्येक आरपीए अभियान को सरकारी संस्था के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ही संचालित किया जाएगा।

किसान सभा ऐप

देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने 'किसान सभा ऐप' विकसित किया है। इसका शुभारंभ 1 मई, 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रबंध निदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने किया।

- **लक्ष्यः** किसानों को सबसे किफायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके, सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना।

चर्चित दिवस			
दिनांक	दिवस/सप्ताह/माह	2020 का विषय	महत्वपूर्ण तथ्य
1 मई	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस	--	इस दिवस की शुरूआत 1886 में हुई थी। भारत में यह दिवस पहली बार 1 मई, 1923 को मद्रास में मनाया गया था।
3 मई	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	'बिना भय या पक्षपात के पत्रकारिता' (Journalism without Fear or Favour)	यह दिवस दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रेस की स्वतंत्रता हेतु जान गँवाने वाले पत्रकारों को याद करने के लिए मनाया जाता है।
5 मई	विश्व अस्थमा दिवस	'इनफ अस्थमा डेथ' (Enough Asthma Deaths)	यह दिवस विश्व भर में अस्थमा के प्रति जागरूकता और देखभाल में सुधार के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (GINA) द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
7 मई	विश्व एथलेटिक्स दिवस	--	एथलेटिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (IAAF) द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। यह दिवस हर साल मई माह में मनाया जाता है, 2020 में 7 मई को यह दिवस मनाया गया।
7 मई	वेसाक दिवस	--	'वेसाक' मई माह में पूर्णिमा का दिन, दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। वेसाक-बुद्ध पूर्णिमा को तिहरे धन्य दिवस यानी तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में माना जाता है।
8 मई	अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस	The dawning of a new era for thalassaemia: Time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to patients	थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर लाल रक्त कोशिका में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता। आरबीसी शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।
8 मई	विश्व रेड क्रॉस दिवस	'कोविड-19 महामारी में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए ताली बजाकर हौसला बढ़ाना'	रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक और शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस (8 मई, 1828) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
9 मई	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	'बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड' (Birds Connect Our World)	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को दो बार मनाया जाता है, ताकि विश्व स्तर पर प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जा सके।
11 मई	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	'रिबूटिंग द इकॉनोमी थ्रू साइंड एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन्स'	देश में नवाचारों और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है क्योंकि 11 मई, 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था।
12 मई	अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस	'नर्स: ए वॉयस टू लीड - नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ' (Nurses: A Voice to Lead - Nursing the World to Health)	यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
15 मई	अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस	'विकास में परिवार: कोपेनहेगन और बीजिंग + 25'	यह दिवस परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक,

			आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रथाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
16 मई	अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस	--	1960 में भौतिकविद् और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है।
16 मई	शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस	--	2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता, समावेशन, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नियमित रूप से संगठित करने हेतु यह दिवस मानने की घोषणा की।
17 मई	विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस	'कनेक्ट 2030: सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईसीटी' (Connect 2030 : ICTs for the Sustainable Development Goals)	वर्ष 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 1865 में इसी दिन अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी और पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
18 मई	अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस	'समानता के लिए संग्रहालय: विविधता और समावेशन'	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना है।
20 मई	विश्व मधुमक्खी दिवस	'बी इनगेज्ड' (Bee Engaged)	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों और धरती को स्वस्थ रखने में आवश्यक भूमिका निभाने के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था।
20 मई	विश्व माप-विज्ञान दिवस	'वैश्विक व्यापार के लिए मापन' (Measurements for global trade)	20 मई, 1875 को 17 देशों ने एक विश्वव्यापी सुसंगत मापन प्रणाली को मान्यता देने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है।
21 मई	संवाद और विकास हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस	--	वर्ष 2001 में यूनेस्को ने 21 मई को संवाद और विकास हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पहली बार यह दिवस 2002 में मनाया गया था।
21 मई	अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस	--	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य चाय के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना है।
22 मई	अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस	'हमारे समाधान प्रकृति में निहित हैं' (Our solutions are in nature)	संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 मई, 1992 को जैव विविधता कन्वेंशन अपनाने के उपलक्ष्य में वर्ष 2000 में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
23 मई	प्रसूति नालव्रण की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस	'लैंगिक असमानता समाप्त करें! स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करें! अब फिस्टुला को समाप्त करें' (End gender inequality! End health inequities! End Fistula now)	संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला या प्रसूति नालव्रण को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रसूति नालव्रण सबसे गंभीर जख्मों में से एक है, जो बच्चे के जन्म के दौरान हो सकता है। इस स्थिति में एक महिला के जननांग पथ और उसके मूत्र पथ या मलाशय के बीच एक असामान्य छेद हो जाता है।
23 मई	विश्व कछुआ दिवस	--	यह दिवस गैर-लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू द्वारा मनाया जाता है। इसे वार्षिक रूप से लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके प्रयावासों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
25 मई	विश्व थायराइड दिवस	--	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में तथा इसके नए उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

29 मई	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस	'शांति सैनिकों में महिलाएँ: शांति की कुंजी' (Women in Peacekeeping: A Key to Peace)	इस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत शांति सैनिकों को शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है।
31 मई	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	'युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना'	विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने तम्बाकू महामारी और इससे होने वाली मृत्यु और बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया।

चर्चित पुस्तक

- 'विजयंत एट कारगिल: द बायोग्राफी ऑफ ए वॉर हीरो' (Vijyant at Kargil: The Biography of a War Hero) **-वी.एन. थापर एवं नेहा द्विवेदी**
- 'मोबिलाइजिंग द मार्जिनालाइज्ड: एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स' (Mobilizing the Marginalized: Ethnic Parties without Ethnic Movements) **-अमित आहूजा**
- 'मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो' (Mad, Bad & Dangerous to Know) **-समीरा अहमद**
- 'इंडियाज वर्ल्ड: हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी' (INDIA'S WORLD: How Prime Ministers Shaped Foreign Policy) **-राजीव डोगरा**
- 'रिवाइविंग जॉब्स: एन एजेंडा फॉर ग्रोथ' (Reviving Jobs: An Agenda for Growth) **-संतोष मेहरोत्रा**
- '35 डेज: हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरेवर इन 2019' (35 Days: How Politics In Maharashtra Changed Forever In 2019) **-जीतेंद्र दीक्षित**
- 'वुहान डायरी: डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी' (Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City) **-फांग फांग एवं माइकल बेरी**
- 'इनटू द हर्ट ऑफ द हिमालयाज' (Into the Heart of the Himalayas) **-जोनो लाइनीन**
- 'व्हेन नेहरू लुक्ड ईस्ट: ओरिजिन्स ऑफ इंडिया-यूएस सस्पिसियन एंड इंडिया-चाइना राइवलरी' (When Nehru Looked East: Origins of India-US Suspicion and India-China Rivalry) **-फ्रेंकिन फ्रैंकल**

आपदा/दुर्घटनायें

चक्रवात 'निसर्ग'

अरब सागर से उठा चक्रवात 'निसर्ग' महाराष्ट्र में अलीबाग के निकट टकराने के बाद 3 जून, 2020 को रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नगिरि और सिन्धुदुर्ग जिलों के विभिन्न भागों से होते हुए नासिक को पार कर गया। इस चक्रवात की वजह से पुणे में 2 और अलीबाग में 2 मौते हुई हैं।

- ज्ञात हो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र/क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र/चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने उत्तर महाराष्ट्र से दक्षिण गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए चक्रवात की 'ऑरेंज चेतावनी' (Orange Alert) जारी की थी।



- ऑरेंज चेतावनी में अधिकारियों से 'तैयार रहने' की उम्मीद की जाती है। ऑरेंज चेतावनी के दौरान पूर्वानुमान भारी से बहुत भारी वर्षा (64.5 मिमी. से 204.4 मिमी. तक) का होता है।
- चक्रवात को 'निसर्ग' नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अमांदा'

31 मई, 2020 को अल सल्वाडोर एवं ग्वाटेमाला में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अमांदा' के कारण हुई बारिश की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लापता हो गए हैं।

- तूफान और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुई बर्बादी से हजारों लोग कोरोना वायरस महामारी के बीच आश्रय गृहों में जाने को मजबूर हो गए हैं।

विविध

चारधाम परियोजना के तहत 'चंबा सुरंग'

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत 'चंबा सुरंग' से वाहन रवानगी का उद्घाटन किया।

- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने ऋषिकेश-धरासू राजमार्ग (एनएच 94) पर व्यस्त चंबा शहर (जिला टिहरी गढ़वाल) के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है।
- बीआरओ प्रतिष्ठित चारधाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और इस सुरंग को खोदने में टीम 'शिवालिक' ने

सफलता हासिल की है। इसके निर्माण में नवीनतम 'ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी' का उपयोग किया गया है। सुरंग अक्टूबर 2020 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी।

- चारधाम परियोजना के तहत बीआरओ 250 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है, जो पवित्र तीर्थस्थल गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाएगा।

जीके फैक्ट

✧ लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत एवं तकरीबन 889 किमी. की अनुमानित लंबाई वाली प्रतिष्ठित चारधाम परियोजना की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

'शाही लीची' और 'जर्दालु आम'

मई 2020 में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक 'शाही लीची' और 'जर्दालु आम' की आपूर्ति करने के लिए करार किया है।



- लॉकडाउन के कारण लीची और आम के उत्पादकों को फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने/परिवहन की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- आरंभ में यह सुविधा 'शाही लीची' के लिए मुजफ्फरपुर और पटना के लोगों को तथा 'जर्दालु आम' के लिए पटना और भागलपुर के लोगों के लिए उपलब्ध होगी।
- मुजफ्फरपुर (बिहार) की 'शाही लीची' और भागलपुर (बिहार) का 'जर्दालु आम' अपने अनूठे स्वाद और और हर जगह मांग के कारण दुनिया भर में विख्यात है। शाही लीची और जर्दालु आम को जीआई टैग हासिल है।

साइको-सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैनडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 15 मई, 2020 को कोरोना अध्ययन शृंखला के तहत एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित 'साइको-सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैनडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद' यानी वैश्विक महामारी एवं लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव और उससे कैसे निपटें शीर्षक के तहत सात पुस्तकों के प्रिंट और ई-संस्करणों का ई-विमोचन किया।

चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई, 2020 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी कर कहा था कि विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 साल के वैश्विक प्रयास के बाद संभव हो पाया, जिसमें दुनिया भर के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया और 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया था।

लिपुलेख-धारचूला मार्ग

8 मई, 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित नए मार्ग लिपुलेख (चीन सीमा) - धारचूला (उत्तराखंड) मार्ग का उद्घाटन किया।



- यह सड़क घटियाबगड़ से निकलती है और कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होती है।
- इस मार्ग के पूरा होने से यात्रा एक सप्ताह में पूरी की जा सकेगी, जबकि पहले यात्रा करने में 2 से 3 सप्ताह लगते थे।
- 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क की ऊंचाई 6,000 से 17,060 फीट तक है। इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है।

ई-बुक ' प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड' का विमोचन

केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2 मई, 2020 को नई दिल्ली में ई-बुक ' प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड' का विमोचन किया।

- यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण हैं, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रो. बी बी लाल शताब्दी समारोह समिति के सहयोग से तैयार किया गया है।
- प्रो. लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बैडोरा गांव में 2 मई, 1921 को हुआ।
- वे 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक के रूप में सेवा की है।
- उन्होंने हस्तिनापुर (उप्र), शिशुपालगढ़ (ओडिशा), पुराना किला (दिल्ली), कालीबंगा (राजस्थान) सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की। प्रो. बी. बी. लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था।

कोविड कथा

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 3 मई, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड 'कोविड कथा' लॉन्च की।

संस्थान–संगठन

प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्थान - संगठन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय

मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार कोविड-19 से अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।

- UNODC की स्थापना **1997** में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केन्द्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी। यह **मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, उपचार और देखभाल;** मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और कैदियों के बीच एचआईवी की रोकथाम; मानव तस्करी रोकथाम और आतंकवाद से दुनिया को सुरक्षित बनाने में मदद कर रहा है। इसके फोकस क्षेत्र हैं- मादक पदार्थ, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से दुनिया को सुरक्षित करना तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय लिए प्रतिबद्धता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

7 मई, 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों ने 12 भाषाओं में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए परामर्श जारी किये।

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसे रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और **16 जुलाई, 1929** को स्थापित किया गया। पहले इसका नाम 'इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' (Imperial Council of Agricultural Research) था।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। इसका प्रमुख कार्य **कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, और संबंधित विज्ञानों में शिक्षा, अनुसंधान** और उसके अनुप्रयोग के लिए योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक **डॉ. त्रिलोचन महापात्र** हैं।

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई, 2020 को 'मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान' की 165वीं और पहली वर्चुअल कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

- मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान एक **स्वायत्त निकाय** है, जो रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और नीति संगत अध्ययन के लिए समर्पित है। इस संस्थान को **11 नवंबर, 1965** को नई दिल्ली में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का आकलन प्रदान करना है। यह भारत सरकार के **असैन्य और सैन्य अधिकारियों को वार्षिक प्रशिक्षण** कार्यक्रम प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

मई 2020 में रक्षा मंत्रालय के बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नवीन मेडिकल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का सफलतापूर्वक एक पेटेंट फाइल किया है।

- भारत सरकार द्वारा **1953** में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) की स्थापना की गई थी। यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन उपक्रम है। जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से निर्गत होने वाली **प्रौद्योगिकियों, जानकारियों, आविष्कारों, पेटेंट प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना,** विकसित करना और उनका व्यवसायीकरण करना है। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एच. पुरुषोत्तम हैं।

केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान

मई 2020 में केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) का नाम बदलकर 'केन्द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी संस्थान' कर दिया गया है।

- भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना **1968** में भारत सरकार द्वारा चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता के साथ की गई थी। सिपेट का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना रहा है। अब सिपेट **शिक्षण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी समर्थन और अनुसंधान** पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरी तरह से खुद को पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करने की स्थिति में होगा। इसका मुख्यालय **चेन्नई** में स्थित है। **प्रो. एस. के नायक** सिपेट के महानिदेशक हैं। ■■

पत्र–पत्रिका संपादकीय



इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

न तो आगे बढ़ें और न ही पीछे हटें

मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख-सिक्किम में झड़पों के परिणामस्वरूप चीन द्वारा बढ़ाई गई आक्रामकता, कोविड -19 के बाद की दुनिया में वैश्विक क्रम में किसी भी बदलाव से बचने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने का संकेत है। भारत को इस संदर्भ में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के आक्रामक अभियान पहले पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में, फिर सिक्किम में नाकू ला और हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में, को समझते हुए इसका उचित जवाब देना चाहिए।

भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है, जिस पर चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जांच के लिए प्रस्ताव आगे रखा उस पर भी चीन व्यापारिक दबाव बना रहा है। इससे पहले, चीन ने कोविड-19 संकट के शुरूआती दिनों में जानकारी के संचालन और प्रवाह पर अपनी रिपोर्ट को छिपाने के लिए यूरोपीय संघ पर दबाव डाला था। शुरूआत में ही सूचना छिपाने से कई देशों के महामारी के प्रभाव को सीमित करने संबंधित उपायों की क्षमता बाधित हुई। भारत के मामले में, चीन न केवल भारत को WHO में जांच का समर्थन करने से पीछे हटने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा बल्कि यह उन कंपनियों को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों में बाधा डालना चाह रहा है, जो चीन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन भी भारत में चीनी निवेश की बढ़ती जांच से खुश नहीं है। चीन की इस हरकत का दूसरा पहलू यह है कि भारत अब व्यवस्थित रूप से अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जैसा कि चीन कर रहा है।

भारत को अपनी कार्यवाही पर अडिग रहना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए डोकलाम गतिरोध के बाद 'अनौपचारिक नेताओं के शिखर सम्मेलन' (Informal Leaders Summit) में तैयार तंत्र का उपयोग करना चाहिए। साथ ही, इसे चीनी दबाव का सामना करने वाले अन्य देशों के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना होगा। भारत को न तो आगे बढ़ना चाहिए और न ही पीछे हटना चाहिए।

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

विषाक्त आपदा: विशाखापत्तनम गैस रिसाव

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास एक विषाक्त रसायन का विनाशकारी रिसाव जिसमें कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों बीमार हो गए, एक लंबे समय से तालाबंदी से जूझ रहे देश के लिए एक झटके के समान था। गोपालपट्टनम के आसपास बस्तियां, जहां एलजी पॉलिमर संयंत्र स्थित है, में रात में ही स्टाइरीन गैस वाष्प के रूप में फैल गई, जिससे लोगों की भागने की कोशिश के कारण कई मौतें हुईं और कई बेहोश होकर गिर गए। पॉलिस्टाइरीन उत्पादों का उत्पादन करने वाले आपदा-ग्रस्त संयंत्र में मौजूद रसायन स्टाइरीन खतरनाक रासायनिक नियमों, 1989 के विनिर्माण, भंडारण और आयात की अनुसूची में शामिल है। नियमों में सख्त मानदंड विनिर्दिष्ट हैं कि, इसका कैसे प्रयोग किया जाए और इसे कैसे भंडारित किया जाना चाहिए। घटना किस कारण से हुई हालांकि यह एक जांच का विषय है। कंपनी और राज्य सरकार को भी पता था कि गैस की विभिन्न स्थितियों में खराब स्थिरता (Poor stability) विस्फोटक स्थितियों को जन्म दे सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी भंडारण संरचनाओं में निर्मित सुरक्षा तंत्र दोषपूर्ण था। क्या कारखाने में फिर से काम की शुरूआत अकुशल लोगों के भरोसे छोड़ दी गई थी? जवाबदेही तय करने के लिए इन पहलुओं की जांच होनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार को उन लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं पर तुरंत ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो गैस रिसाव से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक हानिकारक रसायन के रूप में, स्टाइरीन तत्काल लक्षणों से परे कैंसर कारक हो सकता है। पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल भुगतान और मुआवजा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की उच्चतम गुणवत्ता तक पहुंच।

गोपालपट्टनम में जो हुआ वह भारत के उद्योगों के लिए भी एक चेतावनी है। इसके लिए किसी विशेष चीज पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि औद्योगिक रसायनों की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, जिसमें छूट के लिए कोई गुंजाइश न हो।

जैसा कि भारत ने एक व्यापक विनिर्माण आधार का लक्ष्य रखा है, उसे सार्वजनिक और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता है। पारदर्शी निरीक्षण औद्योगिक विकास के लिए बाधा नहीं है, बल्कि यह भयानक खामियों को दूर करके सतत विकास को सुनिश्चित करता है।

स्रोत- द हिंदू

एक दोहरी आपदा: कोरोना वायरस के बीच एक चक्रवात

चक्रवात अम्फन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मृत्यु और तबाही का जो मंजर दिखा, उसने एक बार फिर तूफान के सीजन के दौरान पूर्वी तटीय राज्यों की नाजुक स्थिति को उजागर किया है। बंगाल में कम से कम 72 लोग मारे गए तथा कोलकाता और दोनों राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लाखों की तादाद में सामान्य जन-जीवन प्रभावित हुआ है। विश्वसनीय पूर्वानुमान और राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल इकाइयों द्वारा तैयारी के लिए उठाए गए कदमों के बाद भी तूफान का प्रभाव विनाशकारी रहा है। पूर्वी तटीय राज्यों में श्रेणी 3 और उससे ऊपर के तूफान के लिए एक संहिता विकसित की गई है, जिसमें निकासी (Evacuation), पावर बैकअप (बिजली) की व्यवस्था करना, लोगों को तटों से दूर रहने की चेतावनी देना, मजबूत इमारतों को चक्रवात आश्रयों के रूप में चिन्हित करना, और चिकित्सा के अलावा कम से कम एक सप्ताह तक पके हुए भोजन की आपूर्ति करना शामिल है। इस बार केंद्र और प्रभावित राज्यों की सरकारों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती यह थी कि हजारों लोगों को भीड़-भाड़ वाले आश्रयों में ले जाया गया, जहां कोविड-19 महामारी का लगातार खतरा बना हुआ है। इसलिए साफ-सफाई की प्रथाओं का पालन करना, वायरस के कारण चिकित्सा सहायता और परीक्षण की आवश्यकता वाले लोगों की निगरानी करना प्राथमिकता में रहा।

भारत की चक्रवात चेतावनी प्रणाली ने स्पष्ट चेतावनी प्रदान करने और जन-सुरक्षा में सक्षम होने में काफी प्रगति की है, लेकिन लाखों नागरिकों को एक बार फिर एक गंभीर आपदा का सामना करना पड़ा है। उत्साहजनक रूप से, कोलकाता हवाई अड्डे की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को चक्रवात के एक दिन बाद बहाल कर दिया गया था, जिससे आवश्यक आवाजाही की सुविधा हो गई, लेकिन असली चुनौती बाहरी क्षेत्रों जैसे कि सुंदरबन में सुरक्षित आश्रय के लिए पूर्व-निर्मित सुविधाएं प्रदान करना है।

हालांकि, वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी या बाद में जीती ही जा सकती है, लेकिन भारत को अपनी तट रेखा पर प्रायः होने वाले इन तूफानों से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमताओं (Response capabilities) को मजबूत करना होगा।

स्रोत- द हिन्दू

राहत की बात: आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

कोविड-19 राहत पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की अंतिम किश्त की घोषणा के साथ सरकार द्वारा आसान शर्तों पर पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाकर एक मजबूत आपूर्ति-पक्ष को बढ़ावा देने, किसानों और श्रमिकों से लेकर व्यवसायों तक सभी क्षेत्रों को सशक्त करने और सबसे महत्वपूर्ण, राजकोषीय क्षति को जितना संभव हो सके कम से कम रखने का दृष्टिकोण दिखाई दिया। जिस स्तंभ पर यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज टिका हुआ है, वह तरलता समर्थन (liquidity support) है, ताकि बिजनेस को फिर से पटरी पर लाया किया जा सके और आर्थिक विकास के पहिये को गति दी जा सके। सरकार ने मनरेगा के लिए बजट को दो-तिहाई बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर अच्छा काम किया है। प्रवासियों के अपने गांवों में लौटने पर, मनरेगा का सार्थक कार्यों के लिए लाभ उठाया जा सकता है। उच्च उधार सीमा के लिए राज्यों की मांग को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कृषि विपणन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने, निजी भागीदारी के लिए अधिक क्षेत्रों को खोलने, रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने, मौद्रिक आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण करने पर जोर दिया है। इन घोषणाओं का कितनी गंभीरता से पालन किया जाता है, इसे देखना होगा।

पैकेज की कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, हालांकि समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करना असंभव है, विशेष रूप से एक महामारी की स्थिति में, यह कहना होगा कि सरकार ने उधार लेने से इनकार करने और मांग बढ़ाने पर अधिक खर्च करने के लिए एक साहसिक दांव लगाया है। यदि आपूर्ति को बढ़ाने की रणनीति कारगर रही, तो यह ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो सरकार को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

स्रोत-द हिन्दू

श्रम के लिए अवमानना: श्रम कानूनों को कमजोर करना

ऐसे समय में जब सभी को वैश्विक महामारी के कारण होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के अंत का इंतजार है, मजदूरों और श्रमिकों के हितों का एक बार फिर बलिदान होना तय है। लगता है कि भारत में राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों में नई जान फूंकने का नया तरीका ढूंढ निकाला है, जो श्रम कानूनों में अतिवादी परिवर्तन का है। लॉकडाउन के बाद व्यापार और आर्थिक गतिविधि को तेज करने के उद्देश्य से कारखानों, उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरों और कर्मचारियों की रक्षा करने वाले कानूनी प्रावधानों से व्यापक छूट देकर इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं।

यह सिलसिला मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा से शुरू हुआ, जिसमें नई स्थापित होने वाली इकाइयों को अगले 1,000 दिनों तक श्रम कानूनों के अनुपालन में काफी छूट दी गई है। इसके अलावा दैनिक काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जाने का प्रावधान भी है। उत्तर प्रदेश ने तीन साल तक सभी श्रम कानूनों को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कामगारों की सुरक्षा, महिला कल्याण और वेतन संबंधी कुछ प्रावधान ही इन पर लागू होंगे।

राज्य में श्रम कानूनों के संचालन के तरीके में बदलाव के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता हो सकती है। एक आशा है कि केंद्र, जो मजदूरी, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के लिए समेकित कोड के माध्यम से एक श्रम सुधार एजेंडा का पालन कर रहा है, श्रमिकों के अनुकूल कानूनी सुरक्षा उपायों से ज्यादा छूट के लिए आसानी से सहमत नहीं होगा। भारत को श्रम कानूनों में बदलाव की जरूरत है, लेकिन कोई भी कानून-हीन राज्य नहीं चाहता है, जिसमें नियोक्ता जो चाहे कर सकते हैं। मजदूरों को पूरी तरह नियोक्ताओं की दया पर छोड़ना सुधार का बिंदु नहीं है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन साधना और उन्हें सुरक्षित रखना अहम है। स्रोत- द हिन्दू ■■

समसामयिक प्रश्न

इस खंड के अंतर्गत इस माह की समसामयिक घटनाओं पर आधारित संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को समसामयिक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

1. 'वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद' भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च निकाय है। इस परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(a) 2009 (b) 2010
(c) 2011 (d) 2012

2. मई 2020 में किसने शीघ्र ही राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस 'भारतमार्केट' लांच करने की घोषणा की?
(a) फिक्की (b) भारतीय उद्योग परिसंघ
(c) अखिल भारतीय व्यापारी संघ
(d) वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

3. जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी प्रदान की। नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपये तक के निवेश वाले एमएसएमई को 'सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाई' के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
(a) 1 करोड़ (b) 2 करोड़
(c) 5 करोड़ (d) 10 करोड़

4. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत 'फंड ऑफ फंड्स' (एफओएफ) के माध्यम से एमएसएमई के लिए कितने रुपये की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई?
(a) 10,000 करोड़ (b) 20,000 करोड़
(c) 30,000 करोड़ (d) 50,000 करोड़

5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन 'टिड्डी चेतावनी संगठन' का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(a) फरीदाबाद (b) जयपुर
(c) गांधीनगर (d) गंगानगर

6. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने परिव्यय के साथ 'रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना' को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है?
(a) 200 करोड़ रुपये (b) 400 करोड़ रुपये
(c) 500 करोड़ रुपये (d) 1000 करोड़ रुपये

7. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मई 2020 में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की। कौन सा शहर 5-स्टार रेटिंग वाले शहरों में शामिल है?
(a) अहमदाबाद (b) भोपाल
(c) सूरत (d) रायपुर

8. किसके सहयोग से पूरे भारत में आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम 'गोल' का शुभारंभ किया गया?
(a) फेसबुक (b) गूगल
(c) माइक्रोसॉफ्ट (d) नीति आयोग

9. मई 2020 में 'सोहराई खोवर पेंटिंग' को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबन्धित है?
(a) बिहार (b) झारखंड
(c) ओडिशा (d) छत्तीसगढ़

10. मई 2020 में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 संपन्न हुई। यह कौन सी सभा थी?
(a) 73वीं (b) 74वीं
(c) 75वीं (d) 76वीं

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' लॉन्च किया है। यह पहल किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित की गई थी?
(a) रूस (b) कोस्टा रिका
(c) फ्रांस (d) ब्राजील

12. विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है?
(a) स्विट्जरलैंड (b) डेनमार्क
(c) फिनलैंड (d) स्वीडन

13. पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किस भारतीय नौसेना पोत में मिसाइल पार्क 'अग्निप्रस्थ' की आधारशिला रखी गई?
(a) आईएनएस कलिंग (b) आईएनएस जलाश्व
(c) आईएनएस केसरी (d) आईएनएस मगर

14. किसके द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमता-आधारित चैटबोट 'पाई' (PAi) लॉन्च किया गया?
(a) पेटीएम (b) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
(c) फ्लिपकार्ट (d) अमेजन

15. मई 2020 में किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम 'निगाह' शुरू करने की योजना बनाई है?
(a) मध्य प्रदेश (b) गुजरात
(c) उत्तर प्रदेश (d) हिमाचल प्रदेश

16. मई 2020 में किस राज्य द्वारा 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' का शुभारंभ किया गया है?

(a) पंजाब (b) महाराष्ट्र
(c) छत्तीसगढ़ (d) कर्नाटक

17. हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबन्धित थे?
(a) सिनेमा (b) लेखन
(c) खेल (d) संगीत

18. भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को किसके द्वारा मई 2020 में दक्षिण एशिया में 'जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक' के रूप में नियुक्त किया गया?
(a) विश्व बैंक (b) यूएनईपी
(c) आईपीसीसी (d) एशियाई विकास बैंक

19. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल प्रदान किया?
(a) नरेंद्र मोदी (b) डोनाल्ड ट्रम्प
(c) किम जोंग (d) शिंजो आबे

20. अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 15 मई (b) 16 मई
(c) 17 मई (d) 18 मई

21. 'मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(a) अमित आहूजा (b) राजीव डोगरा
(c) जीतेंद्र दीक्षित (d) समीरा अहमद

22. मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अमांदा' से प्रभावित रहा?
(a) अल सल्वाडोर (b) पेरु
(c) मैक्सिको (d) ब्राजील

23. केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है?
(a) तरुण बजाज (b) रवीश कुमार
(c) टी.एस. तिरुमूर्ति (d) अरविंद शर्मा

24. देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने मई 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रारंभिक समझौता किया है?
(a) ओएनजीसी (b) सुजलॉन एनर्जी
(c) भारत पेट्रोलियम (d) अदानी पावर

25. ग्रैंड स्लैम विजेता महान टेनिस खिलाड़ी एश्ले कूपर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे?
(a) स्वीडन (b) ऑस्ट्रेलिया
(c) फ्रांस (d) जर्मनी

उत्तरमाला

1. (b)	2. (c)	3. (a)	4. (d)	5. (a)
6. (b)	7. (c)	8. (a)	9. (b)	10. (a)
11. (b)	12. (d)	13. (a)	14. (b)	15. (d)
16. (c)	17. (b)	18. (a)	19. (c)	20. (b)
21. (d)	22. (a)	23. (c)	24. (a)	25. (b) ■

SUBSCRIPTION OFFER
SAMSAMAYAKI CHRONICLE (HINDI)

PLEASE WRITE ON ENVELOP - SUBSCRIPTION

SUBSCRIPTION FEE

1 Year.....Rs. 500/-
2 Years.....Rs. 950/-

Send Rs. 500/- for 1 year subscription & Rs. 950/- for 2 years subscription Current new stand price Rs.30/- × 12 including Regd. post charges

INTIMATE YOUR ADDRESS IN BOLD CAPITAL LETTERS

Enrol me as a subscriber of Samsamayaki Chronicle for.....Year(s).

Name.....
Address:.....
.....
Distt:.....State:.....
Pin:.....Mob.:.....
E-mail:.....
DD/MO No:.....Dated:.....
Bank.....for Rs:.....

Note:

- Magzine will be sent by regd. post under licensed posting.
- Please mention telephone no., email id along with address.
- All Demand Draft should be drawn in favor of Chronicle Publications Pvt. Ltd. and payable at New Delhi. Out Station cheques not accepted.
- Subscription shall start after 45 days of receipt of your payment

Post Your subscription request to:

CHRONICLE PUBLICATIONS PVT LTD
A-27D, Sector–16, Noida: 201301,(U.P.)
Ph.: 0120-2514611-12, Mob.: 09953007629
E-mail: subscription@chronicleindia.in



लोक सभा | राज्य सभा
प्रश्नोत्तर–सार

इस अंक में संसद के बजट सत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का तथ्य सार दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को सरकार की कार्य-योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य-योजनाओं से अवगत कराना है।

लोक सभा

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि: समय-समय पर संशोधित भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत **1 अप्रैल, 2002 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** की स्थापना की गई, ताकि देश के वाणिज्यिक रूप से **अलाभकारी ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों** में दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के क्षेत्राधिकार में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सभी **दूरसंचार सेवाओं** के साथ-साथ **मोबाइल सेवाएं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर केबल** जैसी अवसंरचना का सृजन इत्यादि शामिल है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में **उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन**, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा **झूठे और भ्रामक विज्ञापनों** से संबंधित मामलों से निपटने के लिए **'केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण'** नामक एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

- केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की संरचना से संबंधित नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में **जांच करने और अभियोजन आरंभ करने**, असुरक्षित उत्पाद और सेवाओं को वापिस लेने का आदेश देने और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने के आदेश देने के अधिकार प्राप्त होंगे।

भारत में बाल विवाह: 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित महिलाओं (20-24 वर्ष की आयु समूह में) का प्रतिशत 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) के अनुसार 47.4 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस-4 के अनुसार 2015-16 में 26.8 प्रतिशत रह गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान देश में सूचित बाल विवाहों की कुल संख्या क्रमश: 326, 395 और 501 रही।

- भारत सरकार ने बाल विवाहों को सिर्फ रोकने की बजाय उनका प्रतिषेध करने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कहा जा रहा है।

राज्य सभा

जलवायु मॉडलिंग अनुसंधान और जलवायु विज्ञान: देश में हाल के वर्षों में जलवायु मॉडलिंग अनुसंधान और जलवायु विज्ञान में क्वांटम वृद्धि हुई है। सरकार ने जलवायु से संबंधित नियमित आंकड़ों में अंतर को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। **'राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र सातत्य मिशन'** (National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem) के तहत छह विषयगत कार्य बलों को सौंपे गए कार्य के भाग के रूप में **हिमालयी कृषि**, सूक्ष्म पेड़ पौधों और **जीव जंतुओं तथा वन्य जीवन; वन संसाधन और पादप विविधता,** प्राकृतिक और भू-वैज्ञानिक तंत्रों तथा ग्लेशियरों सहित जल संसाधन के क्षेत्रों में डाटाबेस और अनुवीक्षण क्रियाविधि तैयार की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण प्रबंधन संस्थान: केंद्रीय बजट 2020 में की गई एक घोषणा के अनुसरण में, संस्कृति मंत्रालय देश के सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा/अनुसंधान/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **भारतीय सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण प्रबंधन संस्थान** (IICHCM) स्थापित करने की योजना बना रहा है। नया संस्थान स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI), राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (NRLC) और पुरातत्व संस्थान (ASI) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को **'राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान'** के साथ विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है। नए संस्थान यानी IICHCM की स्थापना संबंधी कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति: वर्तमान में **मसौदा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** पर सरकार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है। इस नीति का विजन **एकीकृत, निर्बाध, कुशल**, विश्वसनीय, हरित, टिकाऊ और **सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं** और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाने वाले लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता को संचालित करना है। मसौदा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ई-मार्केट प्लेस** बनाने का प्रावधान है। यह एकल विंडो पोर्टल विभिन्न लॉजिस्टिल सेवा प्रदाताओं जैसे **ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउसिंग, शिपिंग लाइन्स**, तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं, मालभाड़ा अग्रेषकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों आदि और सीमा-शुल्क सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियां, विनियामक, प्रमाणीकरण और अनुपालन सेवा में शामिल भागीदार सरकारी एजेंसियों आदि के साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। ■■

इन्हें भी जानें



इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्दों से आने वाले संभावित प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

- **ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर:** केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को सभी के लिए ओपन सोर्स कर दिया है। सॉफ्टवेयर को दो व्यापक श्रेणियों, स्वामित्व और ओपन सोर्स (Open Source) में विभाजित किया जा सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे सॉफ्टवेयर के निर्माता से खरीदना या लाइसेंस लेना होता है, उसे 'स्वामित्व या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर' (Proprietary or closed-source software) कहा जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल अर्थ और एडोब फोटोशॉप आदि। इसमें सॉफ्टवेयर खरीदने या लाइसेंस प्राप्त करने पर भी सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार निर्माता के पास रहता है। ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए न लाइसेंस की आवश्यकता होती है और न ही इसे खरीदने की आवश्यकता। इसका सोर्स कोड डाउनलोड करने, जांच करने, पुनर्वितरित करने और बेहतर बनाने हेतु सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर के उदाहरण वर्डप्रेस और मोजिला ब्राउजर हैं।
- **सोनिक बूम:** बेंगलुरु में 20 मई, 2020 को तेज ध्वनि ने लाखों शहरवासियों को हैरान कर दिया था, जो एक भारतीय वायु सेना के सुपरसोनिक परीक्षण विमान से निकली थी। 'सोनिक बूम' एक ऐसी ध्वनि है जो ध्वनि की गति से तेज गति से उड़ने वाले विमान या अन्य वस्तु से उत्पन्न होती है। सोनिक बूम ध्वनि ऊर्जा का भारी मात्रा में उत्पादन करता है, जिससे यह कान में एक विस्फोट या गड़गड़ाहट की तरह लगता है। जब कोई विमान यात्रा करता है, तो यह विमान के आगे और पीछे दबाव की तरंगों की एक श्रृंखला पैदा करता है। ये तरंगें ध्वनि की गति से गुजरती हैं और जैसे-जैसे वस्तु की गति बढ़ती है, वैसे-वैसे लहरें एक साथ या संकुचित होती जाती हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे के पथ से जल्दी नहीं निकल पाती हैं। इसके बाद, वे एक एकल कंपन तरंग में विलीन हो जाती हैं, जो ध्वनि की गति मैक 1 (समुद्र तल पर 1235 किमी/ घंटा) से चलती हैं।
- **स्थानिक बीमारी:** अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, एक बीमारी स्थानिक (Endemic) तब होती है, जब इसकी उपस्थिति या जनसंख्या समूह में सामान्य प्रचलन निरंतर रहता है। जब मामले बढ़ने लगते हैं, तो इसे महामारी (Epidemic) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानिक बीमारी के कुछ उदाहरणों में चिकन पॉक्स और मलेरिया शामिल हैं, जहां दुनिया के कुछ हिस्सों में हर साल इन बीमारी के मामलों की अनुमानित संख्या होती है। 'जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ' में प्रकाशित एक गणितीय मॉडलिंग के अनुसार यदि R0 (जिस दर पर वायरस प्रसारित होता है) 1 के बराबर है, तो बीमारी स्थानिक है। यदि R0 > 1 हो तो इसका तात्पर्य है कि मामले बढ़ रहे हैं और यह रोग अंततः एक महामारी बन जाएगा। यदि R0 < 1 हो तो बीमारी के मामलों की संख्या कम हो रही है। यहां, R0 एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संक्रमित लोगों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें बीमारी है।
- **साइटोकिन स्टॉर्म:** साइटोकिन स्टॉर्म (cytokine storm) प्रतिरक्षा कोशिकाओं और उनके सक्रिय यौगिकों (साइटोकिन्स) का एक अति उत्पादन है, जो एक फ्लू संक्रमण में, अक्सर फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बढ़ने से संबंधित होता है। परिणामस्वरूप फेफड़े की सूजन और द्रव बनने से श्वसन संकट पैदा हो जाता है और रोगी द्वितीयक बैक्टीरियल निमोनिया द्वारा ग्रसित हो सकता है, जिससे अक्सर रोगी की मृत्यु हो जाती है। साइटोकिन स्टॉर्म एक संक्रमण, स्व-प्रतिरक्षा स्थिति, या अन्य बीमारियों के कारण हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में लालिमा और सूजन, गंभीर थकान और मितली शामिल हैं। साइटोकिन स्टॉर्म को 1918-20 के स्पैनिश फ्लू और हाल के वर्षों में 'एच1एन1' (स्वाइन फ्लू) और 'एच5एन1' (बर्ड फ्लू) में मृत्यु दर के संभावित प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है।
- **'डी-10' क्लब:** ब्रिटेन की सरकार ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई को लेकर सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतों के मद्देनजर भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का 5जी क्लब बनाने के लिये अमेरिका से संपर्क किया है। लोकतांत्रिक देशों के इस 'डी-10' क्लब में जी-7 देशों 'ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा' के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत शामिल होंगे। इस समूह का लक्ष्य 5जी उपकरणों के लिये वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना और चीन पर निर्भरता कम करना है।
- **क्रिप्टो-जैकिंग:** क्रिप्टो-जैकिंग अवैध रूप से किसी अन्य के कंप्यूटर का उपयोग करके बिटकॉइन या अन्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। क्रिप्टोजैकर्स आमतौर पर लोकप्रिय वेबसाइटों को निशाना बनाते हैं। एक बार जब मैलवेयर पैच को किसी वेबसाइट पर अंतःस्थापित कर दिया जाता है, तो यह वेबसाइट विजिटर के वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है तथा उनकी मशीनों को धीमा कर देता है। ■■